[Shri Bhupesh Gupta]

there before us for two or three days. All that we had been told before was that the Americans would not supply such heavy weapons to Pakistan. In fact, a previous allegation they had denied. But actually we know that through intermediaries, they are supplying it. The same thing they are doing now. Now, it has been done openly, quite clearly to put pressure on India and to complicate the situation, between India and Pakistan, to create more tension between our two countries, so that nothing goes well. Therefore I think the Prime Minister is well advised, *suo motu*, to make a statement. A motion is there. We all and our names to the motion.

THE UTTAR PRADESH BUDGET (1968-69 GENERAL DISCUSSION) —*contd.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : That will do. Now, we come to the U. P. Budget, but before that I would like to know the sense of the House about the two Bills that were laid on the Table of the House.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : The Bills cannot be taken up today. Why do you take it. The rules do not permit it.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : It is not on the Agenda. Let us not take it up today, because it will be a very bad convention.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Leader of the House agrees

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JAISUKHLAL HATHI) : Madam, I said, in the very beginning, that if only the House wants it, we shall today finish these matters. Otherwise, tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Tomorrow the two Bills. Now the U. P. Budget. Mr. Ansari :

श्री हयातुल्ला अन्सारी (उत्तर प्रदेश) : मैडम डिप्टी चेयरमैन, अभी थोड़े दिनों की बात है जब इलाहाबाद और कलकत्ता के रायट के बारे मे होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था तो मैंने उनसे दो बातें पूछी थी। एक तो यह कि उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद में रायट हुआ है, किसी हिन्दू ने किसी मुसलमान पर रंग डाल दिया था, तो मैने कहा था कि कही यह अफवाह तो नही है, आपने बात पक्की कर ली है या नही । दूसरी बात यह कि आनरेबिल मिनिस्टर ने कहा था कि मौलाना असद मदनी और मौलाना अब्दुल रऊफ इस लिये पकड़े गये थे कि उनके पास कर्फ्यु पासेज़ नहीं था। अफसोस की बात है कि ये जो उनको इन्फर्मेशंस दी गई, दोनों गलत निकली । इसके लिये मै फिर कहूंगा पार्लियामेंट मेम्बर्स के एक डेपुटेशन को जो इलाहाबाद गया था । उसमें है मिस्टर अमृत नहाटा, के० आर० गणश, मि० शशिभूषण, मि० हरिकृष्ण और मि० रामस्वरुप। इन लोगों ने जितना स्टेटमेंट दिया उसमें दोनों बातों को गलत कहा । उन्होंने मैजिस्ट्रेट से पूछा कि क्या हुआ । मैजिस्ट्रेट ने बताया कि एक हिन्दू ने एक मुसलमान पर रग डाल दिया, उस मुसलमान ने पिस्तौल निकाल ली । उन्होने कहा कि वह मुसलमान कौन है, आपने उसे गिरफ्तार किया है, उसका नाम आपको मालूम है । तो मजिस्ट्रेट और पुलिस वाले बैठे थे, कुछ नही बता सके । न वह नाम बता सके न पता बता सके और न कुछ और कर सके। इसी तरह से मौलाना अब्दुल्ल रऊफ और मौलाना असद मदनी की जो गिरफ्तारी हुई है वह भी एक बहुत ही तमाशा सा हुआ है । वाकया दिया है इन हज़रात ने जिनका मैंने अभी तज़किरा किया । वह लिखते है कि ये लोग आधी रात को इलाहाबाद पहुचे और सिविल लाइन्स में अपने एक दोस्त के यहां

टिके जहां कर्फ्यू नहीं था। वहां से उन्होंने मुकामी अफसरान को टेलीफोन किया और मजिस्ट्रेट से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। बाद में अफसरान ने इनसे कहा कि कोतवाली जायं। उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास कर्फ्यू के पासेज नहीं हैं और रास्ता भी नहीं जानते हैं। पुलिस वाले तब फिर खुद उनके पास आए और उनको कोतवाली ले गए। वहां उनको धक्का दे कर एक पुलिस गाड़ी में बैठाया गया और जेल पहुंचा दिया गया।

वह भी सुन लीजिए कि किस किस तरह से किस्से गढे गये हैं और किस तरह से लड़ाई हुई है। मैं अभी यह नहीं बता रहा हूं कि कम्यूनल रायट क्यों हुआ। इसके पीछे पूरी एक पोलिटिकल चाल चली जा रही है और उसकी एक खास गरज है और बाद में मैं उसकी तरफ इशारा करूंगा। तो यह लिखते हैं :

"जब हम इलाहाबाद पहुंचे तो जो बात हमको सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस हुई वह अफवाहों की ज्यादती थी, अजीब व गरीब अफवाहें फैली हुई थीं। हमको बताया गया कि मैजारिटी के एक शख्स की गर्दन काट कर उसको लटका दिया गया है। हमारे दोस्त ने हमको बताया कि उस दिन मैजारिटी के तीन आदमी मार डाले गये हैं। जब पूछा तो पता चला, कि यह तीनों जो लोग थे वह माइनारिटी के लोग थे।

शरणार्थियों ने हमको बताया कि मैजारिटी के ट्रेडर्स की लाखों की जायदाद बर्बाद कर दी गई है लेकिन जब पूछा गया तो बिलकुल गलत मालूम हुआ। एक दुकान लकड़ी की जरूर जली है नान मुसलिम की लेकिन हुआ यह था कि उसके पास ही एक दुकान थी मुसलमान की उसमें आग लगाई गई और आग भड़क कर यहां आ गई और कपड़े की जो दुकान थी नान मुसलिम की वह भी जल गई। लेकिन इस तरह से जो सात दुकानें मुसलमानों की जालई गई तो उसमें एक दुकान वह भी जल गई।"

उनका स्टेटमेन्ट यह है कि आग लगाने वालों ने यह नहीं सोचा कि हवा और आग जो है वह हिन्दू और मुसलमान में तमीज नही करते हैं और इस धोखे मे वह दुकान जल गई। इसके अलावा पहले से दुकानों पर और मकानों पर निशान लगा दिये गये थे और वह जलाए गए।

यह भी सुन लीजिए चमड़े की सबसे बड़ी दुकान, घड़ियों की दो सबसे बड़ी दुकानें, बिसातखाने का बहुत बड़ा गोदाम, पूरी तरह लूट कर, उजाड कर ज़मीन के बराबर कर दिये गए और सब के सब माइनारिटी की दुकानें थीं। इनका नुकसान 25 लाख के करीब हुआ।

इसके बाद जब मजिस्ट्रेट से मिलने गये तो उन्होंने रायट की बातें की और उसमें उन्होंने कुछ कहानियां सुनाई कुछ किस्से सुनाए और उसके कैक्ट्रस के बारे में बहुत कम बताया। उसके बाद उसने कहा कि हमने दोनों को बराबर गिरफ्तार किया है, हिन्दुओं को भी मुसलमानों को भी और उन्होंने पूछा कि मुसलमानों का क्या कसूर है, तो बता नहीं सके। उन्होंने कहा कि एक हिन्दू भी मरा है। पूछा गया : नाम क्या है ? तो यह बताते हैं, कि नाम पूछा तो उस पर तमाम पुलिस अफसर जो मौजूद थे, एक दूसरे का मुह ताकने लगे और एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। आखिरकार हमको बताया गया कि नाम नही जानते हैं इस लिये चार आदमी जो मरे थे चारों मुसलमान थे।

अब यह भी सुन लीजिये जो यहां पर आनरेबिल मिनिस्टर ने कहा हमने अफसरान से पूछा कि फसादाद कैसे शुरू हुये तो

[श्री हयातल्ला अन्सारी]

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि बाज होलियारों ने एक मुसलमान पर रंग डाला, मुसलमान ने फौरन पिस्तौल निकाल कर तान लिया । उस पर मेजारिटी के लोग बिगड़ गये । हमने पूछा कि क्या उस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो जवाब दिया नही । हमने पूछा उस शख्स को जानते हो । जवाब दिया कि जानते है लेकिन बतायेंगे नही । हमने पूछा आप को खबर किस से मिली तो वह जाहिर नही कर सके । पिस्तौल तानने की पूरी कहानी अफसरों ने गढ़ी और फैलाई और जजबात भड़काने के लिये इस्तेमाल की है ।

अब मै दो तीन बाते इसमें की और कहूंगा और उसके बाद अनालिसिस करूंगा कि ये रायट क्यो हो रहे है और रायट क्यो हुये है । इलाहाबाद मे बिल्कुल परपजली रायट कराया गया है । एक चीज यह भी कही गई कि दो जख्मी हिन्दुओं को अस्पताल मे जख्मी मुसलमानों के साथ रखा गया । यह दोनो हिन्दू किसी दूरदराज गांव में होली के सिलसिले मे जख्मी हुये थे और उनको छर्रे से जख्मी मुसलमानों के साथ अस्पताल मे लिटाया गया था ताकि गलत तौर पर यह जाहिर हो कि दोनों फिरकों पर बराबर के मसायब पड़े है । जख्मी कोई वहां हिन्दू था ही नही, जो दो हिन्दू कहीं और जगह से ले आये थे उनको वहां रखा गया था ।

एक और वाकया अस्पताल का है । उन्होंने बताया है कि एक अस्पताल मे जब हमने यह देखा कि चार जखमियो के थकड़ियां पड़ी हुई है तो हम हैरतजदा रह गये । उनमे से एक के चार रोज से हथकड़िया पड़ी थी और तीन के वजीर आजम के उनको देखने आने से एक घटा कब्ल हथकड़िया डाली गई थी । हमने एस० पी० से पूछा कि क्यों डाली गई है क्योकि उनमे से बाज के पैरो पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वह भाग नही सकते, तो वह लोग मुसकराते रहे और ठीक तरह से जवाब नही दे सके ।

इस तरह की बातें बहुत है स्टेटमेंट में लेकिन मैं यह बताऊंगा कि यह फसाद होना था और यह भी मैं बताऊंगा कि फसाद किस लिये कराया गया है । वही एक पार्टी फसाद कराती है और उसी पार्टी के कुछ लोग फिर मुसलमानो से कहते है कि कांग्रेस राज है, इसमें तुम जिन्दा नही रहोगे, मर जाओगे, इस लिये एलेक्शन आये तो हम को वोट देना । टेकनिक यह है कि बैलेंसिंग वोट जो है वह मुसलमानो के पास है और उनको अजीब अजीब तरीके से डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है । तो इलाहाबाद में तो रायट होना था । जब मेरठ में रायट हो चुका था उस जमाने मे तो उनको यह दिखाना था कि यह न समझा जाय कि सिर्फ जनसघ के राज मे रायट होता है बल्कि दूसरे राज में भी रायट होता है और इस लिये इलाहाबाद मे रायट कराया गया ।

एक चीज और भी है कि सब के सब सरकारी अफसर यहा उसी किस्म के कैसे पहुंच गये। क्या आप समझती है मैडम, कि यह बात आप ही आप हो गई । सरकारी अफसरों मे बहुत से अच्छे भी हैं, बहुत से सच्चे और ईमानदार भी है और बहुत से ऐसे है जो यह समझते है कि रायट नही होना चाहिये । मगर यह पहले से प्रिपेयर किया गया था और ऐसे लोगो को वहा पर अप्वाइन्ट कर दिया गया था और पहुंचा दिया गया था । यही नही है बल्कि में इस लिये इस बात को पेश कर रहा हूं कि मैं चाहूंगा लेकिन कोई मिनिस्टर तो मौजूद ही नही है . . .

SHRI G. H. VALIMOHMED MOMIN (Gujarat): Madam, nobody is here of the Home Ministry, and it relates to the riot situation in Allahabad.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Pahadia is in charge of the Budget.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Does anyone know about anything?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): We will try to learn from you.

श्री हयातुल्ला अन्सारी : अब इसमें मुझे एक बात और कहनी है । यह अफसर एक ही जगह नहीं भेजे गये बल्कि इस तरह के कई जिलों को निशाना बनाया गया है । वहां छांट कर ऐसे अफसर भेजे गये हैं जो रायट करा सकते हैं । जो रायट कराने के लिये ऐटमास्फेयर बना सकते हैं । इस वक्त जब कि वहां प्रेसिडेंट रूल है अगर इसका इन्तजाम नहीं किया गया तो मेरे खयाल में और किस्से फैलने जायेंगे और काफी जोर पकड़ेंगे और कुछ भी हो सकता है क्योंकि मिडटर्म एलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं ।

दूसरी एक बात मुझे और कहनी है । उसका सम्बन्ध एक तरह से उत्तर प्रदेश से भी और सेंटर से भी है और वह है मुसलिम युनिवर्सिटी का मामला । पिछली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जैसा काम किया है उसके ऊपर अभी अच्छी रोशनी डाल दी काटजू साहब ने और उन्होंने मैदान तैयार कर दिया । मुस्लिम युनिवर्सिटी का मामला भी पिछली एजुकेशन मिनिस्ट्री का तैयार किया हुआ है । वहां लड़कों ने रायट कर दिया था, बहुत बुरा किया था, बहुत बदतमीजी की थी मगर उसके बाद यह कहा गया कि लड़कों ने पहले से एक साजिश कर रखी थी वाइस चांसलर के मर्डर की । इस साजिश के लिए कोई 30-35 आदमी गिरफ्तार किए गए, लेकिन डेढ़ साल तक कोई केस नहीं चलाया गया । इसमें हमारे बहुत बड़े-बड़े आदमियों को गिरफ्तार किया गया, ऐसे बड़े-बड़े नेशनलिस्ट आदमियों को बदनाम किया गया जिन्होंने एजूकेशन की सर्विस की, ऐसे स्टुडेन्ट्स को फंसाया गया जिनका कोई हिस्सा उसमें नहीं था । इस तरह मुस्लिम युनीवर्सिटी की पोजीशन बहुत बिगाड़ दी गई । इलेक्शन में यह चीज बहुत चली और इसने बहुत असर डाला ।

इस वक्त भी उसका प्राब्लम बहुत टेढ़ा है कि अभी तक उसका बिल नहीं आया है और हमको नहीं मालूम कि किस बेसिस पर यह आने वाला है लेकिन मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि मुसलमान गवर्नमेंट ने इस बात को कमिट किया है कि यह अकलियती इदारा है, माइनारिटीज का इंस्टीट्यूशन है और यह प्रेसिडेन्ट ने कमिट किया है, जितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उन्होंने कमिट किया है और खुद एजूकेशन मिनिस्टर ने कमिट किया है । मैं चाहूंगा कि इसके लिए बिल जल्दी आए ताकि फैसला हो जाए । दूसरी बात, यह बेहतर होगा कि बिल के आने से पहले जनरली मुसलमानों को कन्सल्ट कर लिया जाय कि किस तरह चाहते हैं । जाहिर है कि गवर्नमेंट रेस्पांसिबिल होगी, गवर्नमेंट उसको कन्ट्रोल करेगी, लेकिन उसकी बनावट क्या होनी चाहिए । अगर वह अकलियती इदारा है तो किस अन्दाज से चले । इसलिए बिल जल्दी भेज दिया जाय, मुसलमान एजूकेशनिस्ट्स, और दूसरे लोग जो, इन्टरेस्ट रखते हैं उनको बिठाया जाय, कोई कमेटी बना दी जाय, कमेटी के सामने इसको सार्ट आउट किया जाय और उसके बाद बिल की जो शक्ल आ जाय वह हाउस के सामने आए । इसमें देर नहीं होनी चाहिए । यह मामला यूनीवर्सिटी के ऊपर फांसी की तरह लटक रहा है, इसे जल्दी तय होना चाहिए ।

दो बातें और पाइन्ट आउट करूंगा । उत्तर प्रदेश में एजूकेशन क्या बन गई है ? वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ का एक आर्गेनाइजेशन बन गया है और यह पोजीशन पैदा की गई है कि राष्ट्रीय स्वयं-

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

सेवक संघ के जो स्टूडेन्ट्स पढ़ते-लिखते नही हैं उनको फर्स्ट क्लास मे पास किया जाय । एजूकेशन कमेटी में उनको भर दिया गया है, परचो के सेट करने की शक्ल बदल दी गई है । मैं चाहूंगा कि इसकी थारो इन्क्वायरी होनी चाहिए । एजूकेशन की ऐसी सूरत न बनाई जाय कि वह एक पार्टी का घर हो जाय जिसको चाहे बिगाड दे ।

दूसरी खतरे की चीज यह है कि उत्तर प्रदेश शक्कर के प्रोडक्शन का बहुत बड़ा सेन्टर रहा है वहां शुगर मिल्स खोली गई हैं, केन की काफी अच्छी पैदावार है, उसको तरक्की दी गई है, लेकिन दो साल मे शुगर का प्रोडक्शन गिर रहा है । पिछली दफा इसलिए गिरा था कि पानी अच्छा नहीं बरसा था, लेकिन इस बार पानी अच्छा पड़ा है लेकिन न शुगरकेन अच्छा पैदा हुआ है और न उम्मीद है कि शुगर का प्रोडक्शन अच्छा होगा । एक काज यह भी है कि जो उम्दा किस्म की, सीड आ गई है गेहूं की, ये लोग उसको बोते हैं, उसमें ज्यादा पैदावार होती है । दूसरा यह है कि पानी का इन्तजाम ठीक नही रहा है । शुगरकेन के लिए यह भी दुशवारी है । एक बहुत बड़ी चीज यह है कि शुगरकेन की कमी होगी उत्तर प्रदेश मे तो उसका नुकसान हमारी स्टेट को ही नहीं पहुंचेगा बल्कि तमाम हिन्दुस्तान को पहुंचेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके लिए थारो इन्क्वायरी होनी चाहिए, कोई कमेटी बनाई जाय जो पूरे प्राब्लम को देखे और ऐसी शक्ल पैदा करे कि शुगर का प्रोडक्शन गिरे नहीं बल्कि बढ़ता चला जाय । अगर हाई-ईल्डिंग वेराइटी आ सकती है गेहूं की तो शुगरकेन की भी मौजूद है, पानी का इन्तजाम हो जाय । पानी के बारे मे सबसे बडी दुश्वारी यह है—पिछली तकरीर मे जैसा मै बता चुका हूँ—कि यू० पी० मे पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने ट्यूबवैल के लिए फेसिलिटीज दी थी उनमे एक यह भी थी कि आधे मील तक जितने पोल लगाए जाएंगे—चार फर्लांग तक—वे फ्री लगाए जाएंगे लेकिन नई गवर्नमेंट जो आई उसने यह फैसिलिटी विदड्रा कर ली । उसने हर फर्लांग पर एक हजार रुपया लगा दिया । इसका नतीजा यह हुआ कि चार फर्लांग पर चार हजार रुपए देने पड़ते थे । पैसे लिए जाने का दूसरा असर यह हुआ कि डीजल इंजन खूब बिके । लोगों ने सोचा कि चार हजार रुपए इधर लगाएं तो उधर क्यों न लगाएं, पूरा इंजन मिल जायगा । यह बात सामने थी टैक्स लगाने वालों के या नही थी, जैसे चाहे समझा जाय लेकिन इससे यह जरूर हुआ कि डीजल इंजनों की बिक्री बेइन्तहा बढ़ गई । कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि डीजल इंजन होंगे तो डीजल की कैसे सप्लाई होगी, उसमें बहुत सी दुश्वारियां होंगी, नही मिल सकेगा तो उन्होंने ट्यूबवेल का आइडिया छोड़ दिया । फिर यह भी हुआ कि पानी बरस गया । पानी बरस जाता है तो लोग ट्यूबवेल की बातें कम सोचते है । इन चीजों मे बहुत नुकसान पहुंचा है शुगरकेन इनडस्ट्री को । मैं यह भी चाहूंगा कि इसकी थारो इन्क्वायरी हो, एक कमेटी बिठाई जाय, उसमें एक्सपर्ट्स भी हों क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा है और हमारी स्टेट को बहुत नुकसान हो रहा है ।

एक चीज जो मुझे और कहनी है वह है हिन्दी की तहरीक के बारे में जो उत्तर प्रदेश मे चलाई गई थी । खास पार्टियों ने चलाई थी—उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है । उन्होंने अपना दामन झाड़ लिया, उससे अलग हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश मे उससे कड़वाहट पैदा हो गई है । वहा भी दूसरी स्टेट्स के लोग मौजूद हैं, उनके स्कूल हैं, कालिज हैं, वे अपनी जबाने बोलते हैं—इससे वहा एक नई कड़वाहट पैदा हो गई है । इस के लिए जब तक कोई खास कोशिश नही की जायगी वह दूर नही होगी । यह एक नई चीज शुरू हो रही है

उत्तर प्रदेश में । हिन्दू-मुस्लिम टेंशन तो था ही, अब एक यह हिन्दी टेंशन और पैदा हो गया—जैसे कि एन्टी-हिन्दी टेंशन साउथ में चल रहा है । मुझे डर है कि हिन्दी और एन्टी-हिन्दी एजीटेशन उत्तर प्रदेश में ही न चलने लगे बंगाल के और साउथ के लोगों में तो टेंशन है ।

मैं चाहूंगा कि यह चीज भी क्लियर कर दी जाय कि उत्तर प्रदेश की पालिसी इसमें क्या है । दूसरे, थ्री-लैंग्वेज फार्मूले को और ज्यादा बढ़ाया जाय और ठीक किया जाय । अब तक फार्मूला जैसे चला है उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा । उसका सारा जोर संस्कृत पर था, हिन्दी लो, संस्कृत लो और अंग्रेजी लो । संस्कृत भी कम्पलसरी है हिन्दी के साथ । ठीक है संस्कृत हिन्दी के साथ पढ़ा दी जाय—मुझे उसकी मुखालिफत नहीं है, उसको ड्योढ़ा कर दिया जाय, बढ़ा दिया जाय लेकिन चीज यह है कि थर्ड लैंग्वेज वह होनी चाहिए जो इण्डिया से कक्नेशन पैदा कर सके, लिंक लैंग्वेज तो हिन्दी है ही लेकिन वह लैंग्वेज ऐसी हो जो दूसरों से मुहब्बत पैदा कर सके और जो टेंशन पैदा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वह दूर हो सके । मैं चाहूंगा कि इसमें साउथ इण्डिया की लैंग्वेज हो, मैं चाहूंगा कि इसमें उर्दू को भी अच्छी जगह दी जाय । जो पिछली गवर्नमेंट थी, नान-कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने जबानी बातें की लेकिन इस बारे में बेइन्तहा उसकी मुखालिफत रही है । हमारे कांस्टीट्यूशन में दो दफा हैं 345 और 347 । 345 में अगर स्टेट चाहे तो किसी जबान को रिकागनाइज़ कर सकती है और 347 में सेन्टर कर सकता है । यू० पी० गवर्नमेंट चाहती थी कि उर्दू की जितनी तहरीक चल रही है वह चलती जाय सेन्टर के खिलाफ और उनका दामन छूट जाय । उसके लिए उन्होंने चालें चलीं, एटमासफियर खराब किया । मैं चाहूंगा कि अब जब प्रेसिडेन्ट का रूल है तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय । थैंक यू ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2·00 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, [THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair].

2 P. M.

श्री तारकेश्वर पांडे (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन है । उत्तर प्रदेश में सबसे विचारणीय विषय है जो इस महान् सदन को विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य राज्यों से पीछे होता चला जा रहा है । यह बजट जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं—औद्योगिक मन्दी है, बेकारी है, आर्थिक और राजनैतिक अस्थिरता है जिसको अगर अराजकता कहें तो अतियुक्ति नहीं होगी ऐसे समय में यह जो बजट है—वह आम जनता को और पढ़े लिखे लोगों को अनुप्राणित नहीं कर पा रहा है, कोई निर्देश नहीं देता है, हमारे जीवन में और हमारे जीवन की समस्याओं में कोई वृद्धि नहीं करता है जिससे कि हम आगे बढ़ सकें । यह बजट न तो समाजवादी है और न जनप्रिय है । मैं चाहता हूं कि वस्तुस्थिति को आप देख लें, तभी हम किसी विकल्प पर पहुंच सकेंगे । किसान, खेतिहर मजदूर और कारखाने का मजदूर, इनकी स्थिति को, इनके स्तर को, कहां और किस स्थल पर यह ऊंचा करता है और उसको आगे बढ़ने में कहां यह मदद देता है ? यह हमको दीख नहीं पड़ता है । उत्तर प्रदेश जो है, उसके सीमावर्ती जितने राज्य हैं, उनसे उसका लगान अधिक है भूमि के ऊपर और अलाभकर जोतों के ऊपर लगान रखा हुआ है । तो इससे किसानों की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि

[श्री तारकेश्वर पांडे]

प्रदेश का पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्र, ये परम्परागत उपेक्षा की नीति के शिकार हैं, केन्द्रीय सरकार के भी रहे हैं और उत्तर प्रदेशीय सरकार के भी रहे हैं और इस बजट में इनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, वही परम्परागत नीति जो रही है वह चालू है । उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने के लिये, उसके जीवन को जागरूक करने के लिये, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, पटेल आयोग की नियुक्ति हुई थी, पटेल आयोग ने इस सन्दर्भ में जांच-पड़ताल की बड़े पैमाने पर और प्रत्येक क्षेत्र में क्या-क्या विकास के कार्य किये जा सकते हैं, उस सम्बन्ध में अपना विवरण दिया । किन्तु, केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार और यह बजट इस समस्या को हल करने के लिये कोई अनुदान न दे रही है और न कहीं आगे काम बढ़ रहा है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय स्तर पर, भारत सरकार ने ऐसे गांवों की तालिका तैयार की है जो कि पिछड़े हुए जिले हैं और उन जिलों में पूर्वांचल के बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया और बस्ती आते हैं । तो उनके लिए विशेष कौनसी धनराशि स्वीकृत की गई है जिससे इनका सुधार हो सके ? इस दृष्टि से यह बजट जो है वह हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है ।

अब, गोरखपुर के सम्बन्ध में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं । विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटक केन्द्र जगह जगह हमारे यहां देश में खोले गए हैं । तो गोरखपुर ऐसा महाप्रदेश है, श्रेष्ठ भूमि है, जिसमें भगवान् बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, उनका धर्म प्रचारित हुआ और अन्तिम समय में उनका निर्वाण, महानिर्वाण, उसी स्थल पर हुआ । वहां पर एक गोरखपुर का बहुत बड़ा ताल है । जिसको सौन्दर्य केन्द्र बनाया जा सकता है, जो कि बाहर से आने वाले लोगों को आकर्षित कर सकता है । हमारे देश का यह दुर्भाग्य है, शासन का भी झुकाव और शिक्षित वर्ग का भी झुकाव यूरोप और अमेरिका की तरफ है, यूरोप और अमेरिका के पर्यटक जब आते हैं तब यह मालूम होता है कि कोई पर्यटक हमारे देश में आया लेकिन सारे एशिया भूखण्ड से बौद्ध धर्मावलम्बी गोरखपुर में आते हैं और उसी से सटा हुआ भगवान् बुद्ध का जन्म-स्थान नैपाल के राज्य में गोरखपुर से बाहर है, तो इसको ध्यान नहीं देते । तो वहां सब कुछ लम्बुनी गार्डेन में हो सकता है । फिर, निकट ही कास्या उनका महानिर्वाण क्षेत्र है, ये जो एशिया खण्ड के यात्री हैं वे वहां आते हैं, धर्म-यात्री आते हैं, बड़े-बड़े शासक जो आते हैं वह वहां जाते हैं लेकिन उनकी सुख सुविधा का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है, कोई बड़ा आधुनिक किस्म का होटल नही है और न कोई सुविधा-जनक सवारी का प्रबन्ध रहता है । इसलिए मेरी यह प्रार्थना थी कि केन्द्रीय सरकार को भारत-स्तर पर इस कार्य को लेना चाहिए लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बजट में इसका कहीं उल्लेख तक नहीं, इसकी उपेक्षा की गई है । जिस गोरखपुर झील का मैंने वर्णन किया है वह एक महान झील है । जैसे नैनीताल है, नैनीताल में पर्यटक जाते हैं और वहां झील में नाना प्रकार से विहार करते हैं और उसके सौन्दर्य से प्रभावित होते हैं उसी तरह गोरखपुर की उस झील को विकसित किया जा सकता है ।

हमसे पहले जो भाई, अन्सारी साहब, बोले हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति के विषय में दो शब्द कहे। यह जो पिछली सरकार थी, मैं स्वयं उसकी शिक्षा नीति से सहमत नहीं था । हमारा राज्य सेक्यूलर स्टेट है और उसके लिये बच्चों के मनोभावों को, बच्चों के मस्तिष्क को इस तरह से विकसित करना होगा जिससे उनमें राष्ट्रीय विचार

बढ़ सकें, पनप सकें, आगे को बढ़ाये जा सकें। पिछली सरकार की नीति, कुछ अंशों में, उसके विपरीत रही है। मैं चाहता हूं कि जगह-जगह जो पब्लिक स्कूल हैं, जिनमें सम्पन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास धन है, सुविधा है, उनमें अच्छे अध्यापक हैं, देश में ऐसे विद्यालयों की, ऐसे विद्या मन्दिरों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश देहातों में बसा हुआ है, ग़रीब है, पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिये कि राष्ट्रसेवक और समाजसेवक उत्पन्न हो सकें और यह शिक्षा देहात के बच्चों को मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही है, शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे गिरता चला जा रहा है। इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूं। कुछ देर पहले मैं डा० काटजू का भाषण सुन रहा था तो स्तब्ध रह गया। मैं समझता हूं कि इस महान वैज्ञानिक संस्था में जो लोग काम करते हैं वह बड़े भाग्यशाली हैं कि हाई स्कूल परीक्षा और इस के समकक्ष पढ़ कर, यदि उच्च पदों पर आसीन होकर अच्छा वेतन पाते हैं तो उन जैसा भाग्यशाली इस देश में कोई नहीं है क्योंकि हजारों की संख्या में आज हमारे इंजीनियर बेकार हैं, उन को कोई काम नहीं मिलता है, और यहां हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति 1600 रु० मासिक वेतन पाता है। तो मैं उसको बड़ा भाग्यशाली मानता हूं, बल्कि मैं यह मानता हूं कि हाई स्कूल पढ़ कर उसने एक ग़लती की। अगर वह न पढ़ा होता तो संभवत: वह 2000 रु० तनख्वाह पा जाता। हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कहा जाता है बिना पढ़ा लिखा जाट पढ़े लिखे से बड़ा होता है और पढ़ा लिखा जाट खुदा से बड़ा होता है। तो उस पुरुष ने ग़लती की। मैं उससे कहूंगा कि अपनी संतान को न पढ़ाओ क्योंकि यह समाजवाद है, यह बड़ा इन्साफ करती है, वह अधिक वेतन देगी।

उत्तर प्रदेश की शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश है। प्रारम्भिक पाठशालाओं में या माध्यमिक पाठशालाओं में जो वेतन उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को मिलता है वह इन सब राज्यों की अपेक्षा कम है। इसलिये हम सोचते हैं कि हमारे राष्ट्रपति तो अध्यापक हैं जो इस बजट को प्रस्तुत करने वाले हैं, और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और जो हमारे केन्द्र के वित्त मंत्री हैं, मेरी यह मान्यता है कि शिक्षा के प्रति उनकी बड़ी अभिरुचि है। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो वेतन कम पाता है वह इस महंगाई के समय में अपने बच्चों को क्या पढ़ा सकता है, जो स्वयं आत्म सन्तुष्ट नहीं है, वस्त्र और भोजन अपने लिये नहीं जुटा सकता है, वह बच्चों को शिक्षा क्या दे सकता है ? तो इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि कोठारी कमीशन ने जो वेतन मान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिये निश्चित किया है वह परिहासमात्र न रह जाय क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसको लागू नहीं किया गया। तो इसको लागू करने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का भविष्य आपके इस बजट में अन्धकारमय है, चिन्तामय है, इसलिये इस दृष्टिकोण से भी यह हमको बल नहीं देता है।

अन्तिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा विशाल, सर्वभारतीय भावना से युक्त प्रदेश है। अभी माननीय अन्सारी साहब ने अपने भाषण में जो कहा उससे मैं तो सहमत नहीं हूं। सम्प्रदाय और भाषावाद की कभी-कभी लहर देश में उठती है। उत्तर प्रदेश में मेरठ और इलाहाबाद में जो साम्प्रदायिक तनाव हुआ वह उचित नहीं है

[श्री तारकेश्वर पांडे]

वांछनीय नहीं है, लेकिन उससे समूचे उत्तर प्रदेश की हम निन्दा नहीं कर सकते । उत्तर प्रदेश इन सब चीजों मे बहुत ऊंचा है, भाषावाद और प्रान्तीयता और साम्प्रदायवाद से उत्तर प्रदेश बहुत ऊंचा रहा है और आज भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है जैसा कि हमारे भाई साहब ने व्यक्त किया है । अभी भी बहुत सर्वभारतीय भावना से ओतप्रोत यह उत्तर प्रदेश है और मुझे आशा है, मुझे इसमें सन्देह नहीं है, कि भारतवर्ष का भविष्य तभी उज्ज्वल हो सकता है जब कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वभारतीय भावना है वही भावना अन्य देशों में प्रचलित हो जाय, उससे सब को प्रेरणा मिल सके और राष्ट्र का निर्माण हो सके । जय हिन्द ।

श्री बी० एन० मंडल (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बजट अभी सदन के सामने है उस बजट को देखने से मालूम पड़ता है कि जब आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को हराया था, उसके शासन को हटाया था, शायद उसका बदला, अब जो वहां राष्ट्रपति के ज़रिए कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसके ज़रिए लेना चाहती है । जो कुछ वहां की जनता ने बीस वर्षों के शासन के बाद कांग्रेस को सजा देने के लिए किया, वह मैं समझता हूं बहुत ठीक किया । अभी भी उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि साक्षरता की जो आल इंडिया की औसत है, वह एवरेज़ भी वहां नहीं है । वहां 20.7 परसेंट तक ही साक्षरता है । वहां के जो देहात हैं, उनकी स्थिति में भी कोई सुधार नहीं है । पूरे के पूरे अभी तक वे ज़ाहिल और पिछड़े पड़े हुए हैं । जो बजट सरकार की ओर से यहां उपस्थित किया गया है, मालूम पड़ता है, इस बजट के ज़रिये जनता को सजा देने की कोशिश की गई है क्योंकि जो वहां का लैन्ड रेवेन्यू था उसको बढ़ा दिया गया है । जो रेवेन्यू 1966–67 में 20.48 करोड़ रु० था वह 1968–69 में बढ़ा कर 22.93 करोड़ कर दिया गया है । उसी तरह से सेल्स टक्स जो कि 1966–67 में 30.12 करोड़ रुपया था वह 1968–69 में बढ़ा कर 39.10 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिससे महंगाई और बढ़ेगी । उसी तरह से स्टैम्प में भी जो 1966–67 में 7.59 करोड़ था वह 1968–69 में बढ़ कर 8.20 करोड़ रु० हो गया है ।

उसी तरह से रजिस्ट्रेशन फी 1966–67 में 1.34 से बढ़ कर 1968–69 में 1.55 करोड़ हो गया है । इधर टैक्सों में जो बढ़ोतरी हुई है वह बढ़ती ही जा रही है और जहां खर्च के जरिये जनता को राहत मिलनी चाहिये थी, उसमें कमी की जा रही है । पब्लिक हेल्थ में 1966–67 में 26.71 लाख था, जो 1968–69 में 5.13 हो गया । इसी तरह से कैपिटल आउट ले कर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में मन् 1967–68 में 11.48 था वह 1968–69 में कम होकर 10.03 ही रह गया है । इसी तरह से इरिगेशन वर्क्स के कैपिटल आउट ले में जहां 1966–67 में 9.39 करोड़ था उसको कम करके 1968–69 में 7.48 करोड़ कर दिया गया है । इसी वजह से आज वहां की जनता में असन्तोष की भावना फैलेगी उसको दबाने के लिये कोर्ट कचहरी का खर्च बढता गया । 1966–67 में 2.77 करोड़ रुपया खर्च होता था, वह अब बढ़ कर 1968–69 में 3.56 करोड़ रुपया कर दिया गया है । पुलिस का खर्च 1966–67 में 16.98 करोड़ था, वह बढ़ कर 1968–69 में 22.60 करोड़ हो जायगा । जेल के सम्बन्ध में 1966–67 में जहां खर्च 2.30 करोड़ रुपया था, वह बढ़ा कर 2.66 करोड़ रुपया कर दिया गया है । इस तरीके से वहां की जो जनता है, उस जनता के ऊपर मालूम पडता है, सरकार का कोप है और सरकार उस जनता को दबाने के लिए तैयार हो गई है ।

गत वर्ष हम लोगों ने देखा कि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था ठीक न होने की वजह से

मिर्जापुर इलाके मे अकाल की स्थिति हो गई थी । इस साल सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए था मगर उसका ध्यान इस समस्या की ओर अब भी नही गया है बल्कि उसने इस चीज के लिये और भी रुपया कम कर दिया है । इस बजट से यह मालूम नहीं पड़ता है कि जो कुछ सरकार संविद इंतजाम कर रही थी जो कुछ उसने कार्य किये थे वह आगे चल सकेगे या नही । और वह किसानों को लगान मे काफी देना चाहती थी , उसके सम्बन्ध मे भी इस बजट मे कोई बात नहीं बनाई गई है ।

सविद की सरकार ने अंग्रेजी को प्रशासन से बिल्कुल हटाने की बात कही थी और वह उस पर अमल भी कर रही थी, मगर इस बजट मे इस तरह की कोई व्यवस्था हमे दिखलाई नही देती है ।

उत्तर प्रदेश तीर्थो का प्रदेश है, इसलिए वहा के लोगों में धार्मिक भावना अधिक है और यही कारण है कि वहा पर जनसंघ की जीत हुई । अभी हाल मे मेरठ और इलाहाबाद मे जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं के पीछे मालूम पड़ता है साम्प्रदायिक भावना काम कर रही है । लेकिन सब से बेचैनी की जो बात है वह यह है कि आज प्रशासन का ढांचा बढ़ता ही चला जा रहा है और उसके साथ जो सरकारी खर्चा है प्रशासन को चलाने के लिए, वह भी बढ़ता जा रहा है । मै चाहता हू कि जनता के जो काम सरकार के द्वारा होने वाले हैं, वे काम जल्द से जल्द पूरे किये जाने चाहिये । लेकिन प्रशासन का जो तंत्र है वह इतना भारी भरकम हो गया है कि उसकी चुस्ती खत्म हो गई है और ढीलापन आ गया है जिस वजह से वह जनता की तकलीफों की तरफ ध्यान ही नही देता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकारी प्रशासन को चलाने मे जो अधिकारी रखे जाते है उनकी संख्या कम से कम होनी चाहिये । जरूरत इस बात की है साधारण जनता को काम की जिम्मेदारी सौपी जानी चाहिये ताकि वह इस बात को महसूस कर सके कि यह जनता की सरकार है और जनता के ही जरिये सरकार चलती है । जनतंत्र की जो परिभाषा है उसमे भी यही बात कही गई है कि जनता के जरिये सरकार को चलना चाहिये । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो प्रशासन है वह नौकरों के द्वारा चलाया जाता है जो हर तरह की गड़बड़ी पैदा करते है । ये सरकारी आफिसर तरह तरह की घूसखोरी और भ्रष्टाचार के कामों में लगे रहते है । इसलिए मैं चाहता हूं कि साधारण जनता को काम दिया जाना चाहिये ताकि इन लोगों के ऊपर सरकार को जो बेशी रुपया खर्चा करना पड़ता है वह न करना पड़े । लेकिन यह बात नहीं हो रही है और मैं समझता हूं कि शायद हो भी नहीं पायेगी क्योकि आज देश मे जो शासन चलता है, वह शासन नौकरशाही के जरिए जो ऊंची जात के है चलाया जाता है । जिन लोगों ने हजारों वर्षों से इस देश में शासन चलाया है, हिन्दुओं के जमाने मे भी इन्ही लोगो ने शासन का कार्य चलाया, मुसलमानों के जमाने में भी इन्ही लोगो ने उनके अधीन रह कर शासन चलाया और अंग्रेजों के जमाने में भी इन्ही लोगों ने शासन का कार्य किया और आज भी वही लोग इस देश का शासन चला रहे है । इन्ही लोगों ने काग्रेस राज्य मे मंत्री और आफिसर बन कर 20 वर्ष तक इस देश का शासन चलाया है । जिन लोगों के संस्कार ही शोषण के आधार पर शासन करने के हों वे लोग किस तरह से देश की जनता की भलाई की बात सोच सकते है । जो आज हमारे देश मे प्रशासन चला रहे है वे किस तरह से अपने पुराने संस्कारों को भूल सकते है और यही कारण है कि आज हमारे देश में जनता की तकलीफों की ओर तवज्जो नहीं दी जाती है । यही कारण है कि आज जनता के ऊपर सरकार को चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है । इसलिये मै चाहता हूं

[श्री बी० एन० मंडल]

कि सरकार के जितने भी कार्य हैं वे जनता के द्वारा चलायें जाने चाहिये । अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो प्रशासन में जो पुराने दुर्गुण हैं वे दूर होंगे और प्रशासन में कुछ नई बात आयेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सरकारी पर्सोनल है उनमे तबदीली लाने की कोशिश की जानी चाहिये ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हू कि जो हमारे देश मे पिछड़े हुए लोग है, पुराने जमाने के पिछड़े हुए है, जैसे आदिवासी, हरिजन, शूद्र और स्त्री इत्यादि हैं, उनकी उन्नति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । इन लोगो का पुराने जमाने से शोषण हुआ है क्योकि मैं यह बात अनुभव से, जो मुझे जीवन में हुआ है, बतला रहा हू । इन लोगो को हमेशा ही सरकार की ओर से तथा जनता की उच्च श्रेणी की ओर से दबाया गया है । आज इन लोगो को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की ओर से इस बात की ओर ध्यान नही दिया जा रहा है । सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से हरिजनो, आदिवासियो और पिछड़े हुए लोगो के उत्थान के लिए प्रशासन मे और हर क्षेत्र के नेतृत्व मे साठ प्रतिशत जगह देने के कुछ नियम बनाये गये थे और कुछ योजनाए बनाई गई थी । मै जो कुछ उन लोगो के सम्बन्ध में कह रहा हू वह कोई ऐसी विशेष बात नही है कि हम इन लोगो पर कृपा कर रहे है । हम इस लिये ऐसा चाहते है क्योकि हम इस देश मे, जनतत्र को मजबत करना चाहते है । इस देश मे जितने लोग है, उनमे ज्यादातर सख्य पिछड़े समाज के लोगों की है । इसलिए यह जरूरी है कि अगर हम देश मे जनतत्री व्यवस्था चाहते है तो इन लोगों को अधिक सख्या मे नेतृत्व का स्थान जल्द से जल्द देना ही होगा । सरकार को यह बात समझ ी चाहिये । अगर हम वैसा करेंगे तो वे भी समझेंग ।क सरकार शुद्ध दिल से हम लोगो को उठाना चाहती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि 60 (साठ) प्रतिशत जगहें इन लोगों के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिएं और जो कुछ भी भलाई के कार्य इन लोगों के लिए हो सकते हैं वे सरकार द्वारा जल्द से जल्द किये जाने चाहिए ।

इस के बाद मैं अब भाषा के बारे में कहना चाहता हू । आज हमारे देश मे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सरकारी कामकाज चल रहा है । हमारे संविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है और हिन्दी भाषा बोलने वालों की संख्या इस देश में और भाषाओ वालों मे अधिक है । यह भी एक कारण है कि सविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकर किया और इसमें ही राजकाज चलाया जाय । लेकिन आज यह बात नही हो रही है । जैसा कि मै पहले ही कह चुका हू कि इस देश का शासन जो लोग चला रहे है वे ऐसे लोग है जिन्होने अंग्रेजों के अधीन रहकर इस देश का शासन चलाया । अंग्रेजी उनकी रग रग मे समायी हुई है । आज वे अपने संस्कारों को कैसे भूल सकते है आज वे ही यह चाहते है कि अंग्रेजी भाषा किसी न किसी रूप मे इस देश मे जारी रहे । सरकार की जो पालिसी होती है, जो उसकी नीति होती है, उस नीति को वे इस ढग से चलाते है जिस मे शासन का काम अंग्रेजी मे ही चलता रहे । ये लोग जनता की भाषा मे घृणा करते है और उस को इस देश मे नही चलाने देना चाहते है । इसलिए मै चाहता हूं कि हिन्दी भाषा द्वारा शासन का सारा कार्य चलाया जाना चाहिये। जनता और शासन के बीच अग्रेजी की दीवार को सुरक्षित रखना चाहते है । अब मै दामो के संबंध मे कु छ बात कहना चाहता हू । रूस मे भी, जब वहां की सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ मे आई, लेनिन जब उसका नेता था, तो सब से पहले उहो ने दामो को ही पकड़ा । दामो पर काबू पाकर ही उन्होने अपने देश की स्थिति को सुधार लिया । आज जिस

तरह से सोशलिस्ट पार्टी कह रही है कि लागत के अनुपात में चीजों के भाव नियत किए जाने चाहिएं, उसकी ओर यह सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है । इस सिलसिले में सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि किसान परिवार का साल भर में जो खर्चा होता है और उसकी उपज में जो खर्चा आता है, इन सब को जोड़ कर और थोड़ा मुनाफा देकर उसकी चीजों के दाम निश्चित किए जाने चाहिएं । उसी तरह से जो उद्योग की चीजें हैं उन पर जो लागत आती है, जो सरकार का टेक्स होता है और जो पूंजीपतियों का मुनाफा होता है, वह दे कर उनका दाम निश्चित होना चाहिए और कृषि और उद्योग की चीजों के दामों में संतुलन रहना चाहिए । अगर ऐसी नीति को अपनाया गया तो उसके साथ-साथ जो आज टैक्सों का सिलसिला है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा । इस ढंग से वैसी नीति का उदय हो सकेगा जिस नीति के जरिए यहां लोगों को राहत मिल सकेगी ।

जहां तक पिछड़ी हुई जातियों का सवाल है, कभी-कभी हमारा मुकाबिला बड़ी जाति के लोगों से होता है । इस सिलसिले में लोग हमसे पूछते है कि आप कहते हैं कि 60 फीसदी ऐसे लोगों को प्रशासन में स्थान देना चाहिए जो कि पिछड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये योग्य नहीं होंगे तो किस तरह से उनके जरिए शासन चल सकेगा । उन लोगों से हम रा यह कहन है कि अगर वे इतने योग्य नहीं है तो भी उनको वहां पर बिठलाइए क्योंकि काम करने से योग्यता आती है । काम करने के सिलसिले मे वे अपनी योग्यता को सुधार लेंगे । हमारा यह भी कहना है कि अगर दूसरे लोग बेशी तेज हैं, बहुत समझदार है तो उनको सेक्रेट्री बन कर, सलाहकार बन कर, उनकी मदद करना चाहिए । इससे उनमें आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी, उनका नैतिक स्तर ऊंचा होगा और इस तरह से देश का भला होगा । तो जो यह कहा जाता है कि जो अयोग्य आदमी हैं, वे कैसे काम चला सकते हैं, उसका एक उपाय तो यह मैंने बतलाया । वैसे हम कहते हैं कि वे अयोग्य नहीं हैं । मान लीजिए अगर कोई मजदूर है और वह शासन में जाता है और उसको कुछ नहीं आता है, तो कम से कम वह अपने स्वार्थ की बात तो करेगा, उसके भाई बन्धु जो हैं, उनके स्वार्थ की तो बात करेगा । वह अगर मजदूरी करता है तो उसके भाई बन्धु की जो मजदूरी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके पास अगर जमीन नहीं है तो उनको जमीन देने की कोशिश करेगा । जिन को अयोग्य समझा जाता है ऐसे लोग अगर शासन में आकर कम से कम यही करना शरू कर दे कि जिन की मजदूरी कम है उनको अधिक मजदूरी दिला दे । जिन के पास जमीन नहीं है उनको ज़मीन दिला दे । अगर इस तरह से काम करने लगेंगे, तो आज हिन्दोस्तान में इस पालिसी से बढ़ कर देश के कल्याण के लिए क्या कोई दूसरी पालिसी हो सकती है । इस लिए उनका जो स्वार्थ है उस स्वार्थ के मुताबिक अगर वे काम करना शुरू कर देंगे तो हम समझते हैं कि उसी से देश का बड़ा कल्याण हो सकता है ।

जो यह बजट अभी आया हुआ है इस बजट के सिलसिले में मैं चाहता हूं कि कोई वहां की राजनैतिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती । अभी वहां पर जो दंगे वगैरह हुय हैं और जब इन्दिरा जी वहां गई है और उस समय जो छात्र आन्दोलन वगैरह हुआ है और उस सिलसिले में जो राजनारायण जी या दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इन सारी बातों का जिक्र उसमें आ पाता । वहां शासन किस ढंग से चल रहा है, उसकी रूपरेखा पार्लियामेंट के सामने या जो लेजिस्लेचर है उसके सामने निश्चयपूर्वक आनी चाहिये क्योंकि राज्य में जो काम होता है उस के

[श्री बी० एन० मंडल]

राजनैतिक महत्त्व के बारे में उस समय जानकारी देनी चाहिये जिस समय खर्चा देने की बात आती है सरकार को ।

श्री नेकी राम (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके ज़रिये अपने साथी वक्ता से यह पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में भी अपोज़ीशन वालों की सरकार रही है और वे जो यह दलील दे रहे हैं कि हरिजनों को जमीन दी जाय, यह अच्छी बात है, मगर हरियाणा में हरिजनों को जो जमीन कांग्रेस की सरकार ने दे रखी थी वह ज़मीन भी अपोज़ीशन वालों की सरकार ने दूसरों को दे दी, तो यह कथनी और करनी में फर्क क्यों है ? जब माननीय सदस्य की सरकार बनी और वह कांग्रेस से ज्यादा नही कर सकी तो वे ऐसी बातें कर के धोखा क्यों देते हैं ?

श्री बी० एन० मंडल : अगर हमारे लोग वहां पर होते तो वे निश्चयपूर्वक अलाभकारी जोत की मालगुजारी माफ कर देते, आप ही बताइये कि हमारे लोग वहां गवर्नमेंट में थे या नही थे ?

इस तरीके से मैं समझता हूं कि अगर कुछ करना है और खास कर के जब कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू है तो देश-कल्याण के लिये इस तरह की नीति बतौर एक्सपेरिमेंट के लागू करनी चाहिये जो अभी वहां पर नहीं लागू की गई है ।

SHRI BALACHANDRA MENON (Kerala): Mr. Vice-Chairman, after the President's Proclamation has been promulgated the State Legislatures are now in a suspended animation. One does not know whether the Legislatures will ever meet. Perhaps you are only waiting to see whether there will be more defections. That position should not be allowed to exist. I would appeal to the Government to see that we go back to the people and find out what they feel about it and let them have their own Government which they like. That alone is going to save the State. Uttar Pradesh is the biggest of our States and is perhaps the one State which gives leaders to the various political parties, the one State which has constantly given us prominent leaders in our national life. Today perhaps that State suffers to the maximum extent, and that is really very unfortunate. All the evils that beset our country find their full expression in Uttar Pradesh, whether it is communalism, whether it is language fanaticism or whether it is backwardness in education. All these things find an unhappy reflection in the worst form in Uttar Pradesh. It is time that Uttar Pradesh must assert itself and must be in a position to have its right place in this democratic life and for that we must spend the maximum amount on education, because without education democracy is not going to be saved. The position is that we have not sufficiently cared to spend to the maximum extent on education. I would therefore request that this budget be so framed that you spend more on education and less on police. But what happens here? I am afraid we are going in the direction of a police State. We spend more and more on police and jails and very little for development, very little for education. This is not the way how it should be done. I would therefore request that we spend more on education, more on agriculture, more on industry and less on other things.

Now on the question of sugar industry itself we find that the industrial magnates have failed to deliver the goods. It is clear that the whole of India depends a good deal for its sugar on the northern States, mainly on Bihar and Uttar Pradesh. We should have a good State sector in the sugar industry. Why should we allow the future in the hands of these private industrialists who have played with the sugar cultivation and

distribution? You cannot expect the cultivators to stick to sugarcane cultivation when they find that it is possible to get better profits if they switch over to some other cultivation. In that case it is better that the State thinks of a big State farm. Why should there not be some model farm? Thereby you will be able to assure sufficient sugarcane to the sugar factories. I would therefore request that the Government seriously considers that suggestion.

Then the question of irrigation has also to be taken up seriously. In the villages there should be more and more tubewells. If the sugarcane cultivation has to improve, proper irrigation facilities have got to be provided. I would therefore request that more money should be spent on such things.

Lastly some enquiry will have to be conducted to find out how far the big officers are really playing into the hands of communal elements. There have been some unfortunate incidents as reported, especially in Allahabad and other places, where Hindu-Muslim tension is mounting up and if certain officers are playing into the hands of such elements, an enquiry will have to be conducted and such officers sacked because that is the greatest danger to our democracy. It has come to a stage where after the going away of British imperialism, even to-day communal elements are coming up and playing with the future of our country. All along we have been blaming it on foreigners and it was so but then there is some other vested interest which is behind it and unless we are very careful about it, the future of our country is going to the dogs. I would therefore request that an enquiry should be conducted and if the officers are found to be playing into the hands of communal elements, drastic action should be taken against them. In the case of education, if we are not serious on secular education, there will be real fear among the Muslims and other minorities. To say that certain sections of minorities are turning out to be communal and it is because of that, that the majority community is also turning out to be communal is no excuse. The communalism of the majority has to be fought by all the secular, political parties and if they do not do so, there is danger because behind the heart of hearts of every one there is communalism. Let us seriously find out whether we are that communal. The biggest injustice will be if you are not going to respect the minorities of our country here. If you are not going to respect the minority Muslims of our country, then woe unto our democracy. I therefore request you to enquire and find out and to take drastic action against any officer if he is found guilty. If the Police Officer or a magistrate, remove him if there is the least tinge of communalism because if they start this mischief, nothing can save us. The political leaders, just for votes, play the dirty game and if the administration also, if the officers are also to do the same thing, what will happen to the poor minorities? One must have greater respect for the minorities. Those belonging to the majority communities are safer because of their numbers. The Hindus are in a majority and are safer. Something drastic has to be done in the case of minorities when they are threatened. Therefore I say that the Government should go to the extent of seriously finding out whether in the Muslim and other minorities in big towns proper help is given. There must be immediate rushing of the police to those places and drastic action taken even if minimum disturbance is there and even the big leader, if he is communal, must be called upon to explain and if there is something dangerous, immediate action against the majority communal leader must be taken. Com-

[Shri Balachandra Menon]

munalism among minorities is different from communalism of the dominant community. The major community has got a responsibility and a definite role to play in this and that will be that it accepts to protect the minorities. I therefore request that an enquiry must be conducted. I am sorry that such things are happening in Allahabad. I believe the political leaders and the communal leaders of the various communities should be asked to come to a definite agreement that they will stand against communalism. Much more than that, the educational policy should be so shaped that secular education will have to be given to the children and every step taken for that. It should not be that anything is done which will make the minorities feel that somehow the influence of the majority communalism is being infiltrated among the other sections through text-books and classes.

PANDIT S. S. N. TANKHA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, it is a sad day for my State of Uttar Pradesh that its Budget for the ensuing year, 1968-69, has come up before this Parliament for its acceptance or rejection instead of its being debated in the Vidhan Sabha of the State at Lucknow as it normally is done and should have been done. I say it is a sad day because what has happened in my State or in some others like Bengal, Haryana, etc. portends, to our shame, signs of breakdown of democracy in our country and with it, the breakdown of our cherished Constitution as well. But let me say that if ever such a thing comes about—I do hope it never will—it will, I am afraid, mean our country also going the way of totalitarianism and dictatorship, the way the rest of Asia has gone and which will mean the end of democracy in the east. Therefore as to what has brought about this sorry state of affairs is a matter of serious concern for all of us, whether in the governing party or the opposition. Let all of us as such, examine coolly what has or is tending to bring about such a state of affairs and I have no doubt that if we give serious thought to it and search our hearts, we shall feel convinced that the responsibility for it, in the main, lies upon the Opposition parties, whether they may have been in existence from before the last general elections or have emerged newly during or after the elections. I am prepared to admit that my own party, the Congress, during its uninterrupted rule throughout the country as one single party for over 15 years may have committed mistakes or gone amiss in certain matters but it cannot be denied that it gave the country a stable Government and an orderly rule of law throughout its tenure of office and I take credit even now that the present Congress Government at the Centre is doing much better than any of the Governments of other complexions in any of the other States. The people in their desire to see if any other political party could give them better living conditions than the Congress regime, voted them to the State Legislatures in greater numbers but still not at the Centre since it has had inherent confidence in the Congress party to be able to meet all the difficult situations better than any other and it is thus that while the Congress is in charge of the Government at the Centre, it has lost its hold in many of the States. Such a situation has also been brought about by the fact that the Opposition parties gave to the electorate false promises which they must doubtless have known, could not be fulfilled by them and which in fact they failed to do. In my State also, the people became a prey to the false hopes and promises of the opposition parties with the result that even though the Congress emerged as the largest single

party in the State and would have succeeded in assuming office and taken the people with them if it had not been for one of its own comrades and tried stalwarts not crossing the floor with some of his men to join and lead the Opposition. And had it not been for his experience, capacity and honesty in running the Government, the Opposition, composed as it was on several different parties with varying ideologies and programmes and ambitions, the non-Congress Samyukta Vidhyak Dal Government in the State would have fallen much earlier than it actually did. During the short period of less than a year that it held office, it was unable to fulfil any of its promises to the people, or to give them a better or cleaner Government and, therefore, it is not surprising the people have lost faith in it and do not regret its going out. But whether they will vote the Congress into office once again or not is yet to be seen. The fallen Government having however failed to find another leader of some eminence to shoulder the responsibility of office in place of its resigning leader, the Governor, whom we all know so very well for his ability and honesty, was left with no choice but to recommend to the President that he may be pleased to assume the administration of the State to himself by suspending the Constitution of the State temporarily with a view to affording the parties an opportunity to settle down and then in a calmer atmosphere to find ways and means to reassume office as soon as they can. I may also say this, Sir, that the reports in newspapers tell us that efforts are again being made by the SVD to find another leader. Perhaps they will succeed, and if they do, the Congress will wish it well. The Congress, as Shri C.B. Gupta, the leader of the Congress Party in the State has clearly stated, is in no hurry to come into office. He has further said that he will be prepared to help the opposition to maintain law and order and to govern better—if they can—so far as it lies in the hands of the Congress to help them.

It is, thus, Sir, that we find that the Budget of the State is here before us for our consideration. But in looking into it we must not forget the fact that the Governor is new to the State and has not had sufficient time to study and formulate it.

Coming now to the provisions of the Budget, I would remind the House that though the State of U.P. is the second biggest State of the Indian Union, it is yet one of the most backward States, not only financially, but also in education, trade, commerce and industry, with little or no mineral resources for its development. It has no industries worth the name except for some old, outmoded sugar mills and a cotton and woollen mill, and a leather factory in Kanpur. During the last Three Five-Year Plans the Central Government too has not helped it sufficiently to develop by providing it with some big industrial or other ventures in the public or private sector, except for a fertilizer factory in Gorakhpur, and a diesel locomotive factory in Varanasi and the antibiotics factory in Hardwar and an aluminium factory in the private sector in Banaras, which have all been set up in the recent past and as such have not yet produced any appreciable effect upon the backward economy of the State, or in removing the poverty of its people.

Being primarily an agricultural State, as mentioned by me earlier, its greatest need is the development of its agriculture, and the setting up of more fertilizer plants and agriculture-based industries in the State. But I do not find

[Pandit S. S. N. Tankha.]

any provision for it in the State Budget, nor any mention of the efforts it is making to induce the Central Government to place more of its public sector undertakings within the State, which efforts are its greatest necessity.

Further I would say that the sugar factories within the State should be helped to change or renovate their plants by giving financial aid for the purpose.

I would also like to draw your attention to a paper mill situated in Lucknow, which, for several years past, is in a very bad state of affairs, its machinery also being very old and outmoded. I am sure, if financial aid is made available to it, it will become an asset for the State. The Minister for Industrial Development should please look into this matter.

I would also like to say, Sir, that efforts should be made to develop tourism in the State to a greater extent. The hill resorts of Mussoorie and Naini Tal, which are very close to Delhi, should be made more attractive, and efforts should be made for the tourists to be in a position to go there in greater and larger numbers. Such places in the Himalayas as Badrinath and Kedarnath, which are some of the finest places on the Himalayas should be made more accessible to the tourists by having an airstrip near about. Some years back, Sir, I saw in the newspapers that efforts were being made by the U.P. Government to have an airstrip at some distance from these places which would still be about three days' journey from Badrinath, but I do not think any tangible result has come out so far.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): Where was it suggested to be situated?

PANDIT S. S. N. TANKHA: I saw mention of the airstrip some years back, but nothing seems to have been done in this direction by the U.P. Government. I would therefore plead with the Minister for Tourism to examine this proposition and to prevail upon the Government to have an airstrip at such a distance so that tourists going from Delhi in the morning could be able to be back here in the evening after seeing those places; otherwise, it would be necessary to have some good hotels there if the tourists are to spend the night at such heights, an arrangement which perhaps will be very costly and difficult to provide.

Then, Sir, there is one other thing about which I would like to mention, and it is about the High Court in Lucknow. Perhaps you may not be aware that Lucknow had a Judicial Commissioner's Court at one time, which later became the Lucknow High Court in 1925. Some years later, under an order issued by the President the High Court of Allahabad was amalgamated with the High Court of Lucknow, and thereafter the two High Courts became one with the stipulation to have a Bench of at least five Judges permanently in Lucknow. Since then this arrangement has continued, and I am glad to say that, instead of having permanently five Judges only, there are now as many as seven or eight Judges permanently sitting in Lucknow to deal with the cases there. But, Sir, now 3 P. M. that the State's administration is in the hands of the Central Government I would plead with the Government that its procedural arrangement should be such that litigants nearer to Lucknow are allowed to file their petitions or appeals before the Lucknow Bench of the High Court instead of having to go all the way to Allahabad.

Under the present arrangement the people from Kumaon who have to pass through Lucknow for going to Allahabad, are compelled to do that in order to file their petitions and appeals in the High Court at Allahabad. They cannot do it in Lucknow. Similarly people from Agra, Meerut and other places in Western U.P. also have to travel all the way to Allahabad. Although these people do not actually pass through Lucknow still they pass through Kanpur which is very close to Lucknow. This arrangement is not at all suitable for the litigants and naturally it causes them inconvenience and hardship and they resent such an arrangement, especially when they know that the High Court at Lucknow and Allahabad is one and the same and there would be no difference if their cases were heard at Lucknow instead of at Allahabad, and which would, in fact, facilitate matters considerably for them. Therefore this aspect of the matter requires attention and I would plead with the Central Government to see that this position is corrected and accepted by the High Court.

In the same connection yet another matter is that after the amalgamation of the two High Courts, the Chief Justice who became the Chief Justice of both the High Courts did one other thing. He removed from the jurisdiction of the Lucknow High Court two or three districts, namely, the district of Faizabad, the district of Pratapgarh and the district of Sultanpur. These districts were taken away from the jurisdiction of the Lucknow Bench. This caused considerable resentment among the lawyers of Lucknow because it greatly affected them professionally. I now understand that two of these districts have been returned to the jurisdiction of the Lucknow Bench, namely, Faizabad and Sultanpur districts, but not the district of Pratapgarh. I would therefore request that the jurisdiction of the Lucknow Bench should in any case be fully restored to it, even if the additional areas of the State that I pleaded for namely, Kumaon and the western regions of U.P. are not made over to the Lucknow Bench of the High Court at this stage.

It has also to be mentioned that the Chief Justice, soon after the amalgamation of the two High Courts also removed certain jurisdictions of the Lucknow Bench to the High Court at Allahabad, namely, the jurisdiction on Company Law matters which since then and up to now cannot be filed and heard in Lucknow. Kanpur, as you know, Sir, is big business centre from where a large number of appeals and cases go to the High Court. But even though Kanpur is only 50 miles from Lucknow the litigants from that place are not allowed to file their appeals or petitions in the High Court at Lucknow. Nor are even the business cases of Lucknow of other cities of Awadh filed in Lucknow. They have all to go to Allahabad. Similar is the position regarding matrimonial cases. Formerly the Lucknow High Court had sufficient matrimonial cases and one Judge was more or less always kept busy hearing matrimonial cases at Lucknow, but now that jurisdiction also has been removed to Allahabad. This is very inequitous and I think the Central Government should take interest in the matter and make the Chief Justice of Allahabad agreeable to accepting some of these suggestions so that both the litigants of public, the State and the lawyers of Lucknow may be benefited by this arrangement.

In the end I will say that I am very glad to find from the Budget papers that the State Government has laid sufficient emphasis on the importance of agriculture in the State. According

[Pandit S. S. N. Tankha.]

to the figures in the Budget, during the year which will end on the 31st of March, 1968, maximum emphasis was laid on agricultural production through high-yielding varieties and as much as 5 million acres were brought under this programme with the expenditures on major and medium irrigation projects which is estimated at Rs. 13·25 crores and Rs. 4·25 crores, an increase in the irrigation potential of the State by 63,000 acres and 1·53 lakh acres respectively is expected. Next year's target for additional irrigation potentiality is 98,000 acres for major and medium schemes and that for minor irrigation scheme is 1·06 lakh acres. The well irrigation has also created an additional 8 lakh acres potential during 1967-68 and private tube-wells and pumping sets energised in 1967-68 is 20,000. This is a very good record of work during the current year. For the next year I find from the Budget papers that the expenditure from revenue is to go up to Rs. 330·74 crores and the excess expenditure of Rs. 6·47 crores will be incurred because of additional dearness allowance which will have to be paid to the Government employees and teachers of aided schools. The capital expenditure of Rs. 36·08 crores is also likly to be exceeded by Rs. 2·89 crores due to larger contribution to the State Cooperative land Development Banks. This is a very good feature of the new Budget. Additional loans of Rs. 6 crores have been granted to the State Electricity Board for energising tube-wells and pumping sets. This thing is very necessary for a purely agricultural State like U.P. Rs. 9 crores have also been allotted for loans to cultivators for the purchase of seeds and fertilisers. The effect of these measures is likely to be that Rs. 7·90 crores will be drawn from the State's reserves. As such I think the Budget has rightly taken into account some of the special needs of the State or at least the agricultural needs of the State. And I have no doubt that the State Government will do its best to provide greater loans to the cultivators for seeds, etc., and more water for cultivating their fields and maintaining their crops. I hope it will also help in energising the electric pumps in greater numbers and also help private individuals in setting up their own pumps. Until some time back—and I think the position is the same now—although there is sufficient energy available in the State, but transmission lines were not sufficient to reach the energy to distant places. Either there was shortage of copper wire or some other difficulties were being experienced because of which use of electric energy for cultivation purposes was not as much as it should have been. Therefore I would impress upon the authorities that this aspect of the matter must be looked into carefully so that the greatest efforts may be by the State to increase its agricultural production and programme in the future.

Then, Sir, as you are aware, the teachers as a whole in all the States are very low paid and they have been clamouring for increases. For some, I believe, increases have been sanctioned but for others it has not been done so far. Further, I find that even though the private schools had been promised that the Central Government would meet their additional expenditure as a result of increased pay to the teachers, many of these institutions have not yet got the benefit somehow or other. Whether it has been because of lack of money provided to them by the Centre or for want of interest by the institutions concerned in making payment of additional salaries to teachers, the fact remains that there is little improvement in their condition.

There is one other matter which I would like to mention and that is about pilgrim traffic to sacred places. You know that the Ganges at Hardwar and Banaras attracts very large crowds, some of them tourists, others pilgrims but mostly pilgrims. The ghats at some of these places are not as well maintained, as they should be. Some years back a programme was undertaken by the State Government for the improvement of the ghats at Banaras but I do not think that the plan has yet been carried out fully. If it has not been carried out it should be fully implemented. Similarly regarding the ghats at Hardwar even though they are better maintained but all the same it seems that the facilities for the tourists visiting that place are not kept fully in mind. Then, Sir, take the case of the ghats at the Allahabad Sangam, for instance. There are not even pucca platforms with steps leading to the Sangam where the waters of the Ganges and the Jamuna meet and because of this people are put to great difficulty and they find themselves sometimes in danger of losing their lives. This matter should be looked into very carefully. I am sure the government will do so and I hope they will make all efforts to look to the comforts of the people visiting these places.

Thank you.

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश का बजट इस सदन में आया है, मैं समझता हूं कि इस बजट को लाने की यहां पर आवश्यकता नहीं थी । यह बजट उत्तर प्रदेश के विधान मंडल में ही पास कराया जा सकता था क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति अभी वहां पर चल रही है, जो वहां की राजनीतिक स्थिति है, जिसमें संविद का बहुमत है, संविद के नेता को चुनने की बात हो चुकी है और समर्थकों की लिस्ट राज्यपाल महोदय को भी दी जा चुकी है। फिर भी वहां पर जनता की सरकार को चलाने न देना, अनावश्यक ढंग से वहां की असेम्बली को भंग करना तथा राष्ट्रपति का शासन लागू करना, यह मुनासिब मालूम नहीं देता है ।

राष्ट्रपति का जो शासन वहां पर लागू किया गया है उसका मतलब परोक्ष रूप में केन्द्रीय सरकार के शासन से ही होता है । वैसी हालत में यह जो बजट लाया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं ।

अब मैं बजट में जो आंकड़े दिये गये ह, उनके संबंध में कुछ बात कहना चाहता हूं । संविद सरकार ने यह फैसला किया था कि जिन लोगों की दो रुपये तक मालगुजारी लगती है, उनकी मालगुजारी बिल्कुल समाप्त कर दी जायेगी और 6½ एकड़ जमीन पर से आधी मालगुजारी उठा ली जायेगी । अगर वहां पर इस समय संविद की सरकार होती तो इस बजट में पिछले साल के मुकाबले में मालगुजारी के आंकड़े कम होते । लेकिन हम इस बजट से यह पाते है कि पिछले साल के मुकाबले से 3 करोड़ रुपया ज्यादा मालगुजारी से वसूल किया जायेगा । इसका मतलब यह हुआ कि जो अनार्थिक जोत वाले किसान हैं, जिनकी खेती से लाभ नहीं होता है, उन किसानों के ऊपर मालगुजारी के जुए को कायम रखने की कोशिश की जा रही है ।

दूसरी फिगर में सैल्स टैक्स के बारे में देना चाहता हूं । आप जानते हैं कि सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका लाजमी नतीजा बाजार की चीजों की कीमत पर पड़ता है और उसका नतीजा यह होता है कि जनता को चीजों के लिए ज्यादा दाम देना पड़ता है । पिछले साल के मुकाबले में इस बार के बजट में 9 करोड़ रुपया ज्यादा सेल्स टैक्स के द्वारा वसूल करने का अनुमान लगाया गया है ।

[श्री रेवती कान्त सिंह]

इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस के संबंध में कहना चाहता हूं। इस में किसान लोग अपनी जमीन को बंधक के रूप में रखते हैं और इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है उस फीस में इस साल अनुमान लगाया गया है कि पिछले साल के मुकाबले में करीब 11 लाख रुपया ज्यादा वसूल किया जायेगा । आप जानते ही हैं कि जब किसान बिल्कुल जमीन बेच देता है, वय कर देता है, तो उस हालत में जो जमीन खरीदता है उसको ही सारा खर्चा देना पड़ता है । जो जमीन रेहन करता है तो खर्चा खदुक को देना पड़ता है । जो बहुत ही गरीब लोगं होते हैं वे ही अपनी जमीन बेचते हैं । इन गरीब लोगों से ही इस बजट द्वारा ज्यादा टैक्स लगाकर वसूल करने की सिफारिश की गई है । लेकिन जब आप दूसरी ओर देखेंगे तो आप पायेंगे कि प्रशासन में पिछले साल के मुकाबले में लगभग 6 करोड़ रुपया ज्यादा खर्चा करने का अनुमान लगाया गया है । जिलों के प्रशासन पर, कोर्ट कचेहरियों पर करीब 1 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च होगा । पुलिस पर करीब 6 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च होगा । जेल पर 36 लाख रुपया ज्यादा खर्च करने का अनुमान है । तो एक ओर टैक्सों में वृद्धि और दूसरी ओर प्रशासन पर अधिक खर्च, इससे यह निश्चित है कि जब टैक्सों में वृद्धि होगी तो जन आन्दोलन शुरू होंगें, चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और सेल्स टैक्स के चलते भी उसके खिलाफ आन्दोलन होंगे और उन आन्दोलनों को दबाने के लिये पुलिस पर, मेजिस्ट्रेसी पर, जेल पर ज्यादा खर्चा करने का अनुमान पहले से लगाया गया है । यह बजट साफ इस बात का दर्पण है, इस बात का साफ सबत है कि इस बजट के द्वारा जनविरोधी कार्रवाइयां होंगी और जन आन्दोलनों को दबाने का काम उत्तर प्रदेश में होगा ।

फिर हम पाते हैं कि जनता की भलाई पर जो पैसा खर्च होना चाहिए उसमें कमी की गई है । पब्लिक हैल्थ पर जितना पैसा पिछले सालों में खर्च होता था उसमें करीब 21 लाख रु० कम करने की योजना है ।

श्रीमन, उत्तर प्रदेश कोस्टल क्षेत्रों से, तटीय प्रदेशों के मुकाबिले में बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है । वहां न ज्यादा कल-कारखाने हैं, न ज्यादा बिजली है न वहां कोई औद्योगिक उन्नति है, उस हालत में भी इंड-स्ट्रीज़ में, उद्योगों में कैपिटल आउटले जितना पिछले सालों में होता था उसमें भी 1 करोड़ 45 लाख रु० की कमी इस साल की गई है ।

श्रीमन् पिछले साल हम लोग जानते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण, पिछले बीस वर्षों में जो सिंचाई को नज़र अन्दाज़ किया गया उसके कारण मिर्जापुर में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अकाल आया था, अभूतपूर्व अकाल आया था । लेकिन इस बजट में भी हम पाते हैं कि पिछले साल के मुकाबिले में 2 करोड़ रु० कम खर्च किया जायगा इरिगेशन के केपिटल आउट-ले पर । कैसे सिंचाई बढ़ेगी, कैसे कारखाने बढ़ेंगे, कैसे खेती बढ़ेगी, इस दृष्टि से भी यह बजट एक निरर्थक बजट है ।

इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के राज्य कर्म-चारियों की समस्याओं की ओर। जिस तरह और राज्यों में, बिहार में, हरयाणा में, पंजाब में काशमीर में राज्य कर्मचारियों की एक मुख्य मांग थी कि केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता मिले और जिसको लेकर वे आन्दोलन चलाते है और चलाते रहे हैं, उस तरह से उत्तर प्रदेश में कर्मचारी भी वर्षों से इस मांग को लेकर आन्दोलन करते रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों

ने लम्बी हड़तालें कीं और उन हड़तालों के फलस्वरूप दर्जनों लोगों को नज़रबन्द किया गया। अभी कल तक उनके नेता श्री गिरीश श्रीवास्तव जेल के अन्दर थे। मुझे आज अखबार में देख कर खुशी हुई कि गिरीश श्रीवास्तव की रिहाई के लिये जो एक आन्दोलन उत्तर प्रदेश से चलने वाला था वह आन्दोलन रुक गया क्योंकि गिरीश श्रीवस्तव की रिहाई कल हो गई। मैंने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की संयुक्त परिषद् के मन्त्री श्री पशुपति नाथ शुकुल का बयान पढ़ा है कि श्री गिरीश श्रीवास्तव की रिहाई हो जाएगी तो हम आन्दोलन स्थगित कर देंगे। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि जब कर्मचारियों ने अपना यह आन्दोलन स्थगित कर दिया है, यह एक गुड जेश्चर है इसका लाभ हुकूमत को उठाना चाहिये। और सीधे कर्मचारियों से वार्ता करनी चाहिये और उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं खास तौर से केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय दर से महंगाई भत्ता देने का सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही सवाल नहीं है, यह तमाम राज्यों का सवाल है। आपको पता है कि पिछली फरवरी में बिहार के कर्मचारियों ने पांच दिन की हड़ताल की थी। हरियाणा में जहां राष्ट्रपति का शासन है वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और दर्जनों लोग नौकरी से निकाले हुये हैं। इस तरह से सारे हिन्दोस्तान में राज्य कर्मचारियों का यह जो आन्दोलन चल रहा है इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये समस्या का समाधान करने के लिये केन्द्रीय सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिये और आगे बढ़ कर के राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देनी चाहिये जिससे राज्य कर्मचारियों को भी केन्द्रीय दर से महंगाई भत्ता मिल सके।

अब मैं उत्तर प्रदेश के शक्षकों के बारे में भी कहना चाहता हूं। अभी उस तरफ के माननीय सदस्य श्री तारकेश्वर पांडे जी ने उनका ज़िक्र किया था। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई लेकिन वह रिपोर्ट देश भर में एक तरह से लागू नहीं हुई। अभी अखबारों में आपने देखा होगा कि 19 मार्च से ही बिहार के शिक्षकों की हड़ताल चल रही है कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को पूरा करने के लिये। अभी आपने दिल्ली में शिक्षकों की हड़ताल को देखा। हरियाणा में भी शिक्षकों की हड़ताल हुई। तो क्या हुकूमत यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश के भी शिक्षक उसी रास्ते पर जाये। ये शिक्षक, ये सरकारी मुलाज़मीन, ये तमाम मध्यम वर्ग के लोग जो स्वभाव से संकोची वर्ग में आते हैं, ऐसे वर्ग के लोगों को भी हुकूमत अपने कड़े रुख से, अपने सहानुभूति पूर्वक रुख से मजबूर करती है कि वे सड़कों पर निकल करके "इन्क्लाब जिन्दाबाद" का नारा लगायें। सचमुच मैं वह दिन बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन होगा जब ये निम्न मध्यम वर्ग के संकोची लोग, ये सरकारी मुलाज़िम, ये शिक्षक सड़कों पर निकल करके नारे लगाने लगेंगे। आप मजदूरों की तरह जब ये मध्यम-वर्ग के लोग सड़कों पर नारे लगायेंगे तो इनका वर्ग बदल जायेगा, इनका करेक्टर बदल जायेगा इनका वर्ग चरित्र बदल जायेगा और तब ये निश्चित रूप से मजदूरों की ओर झुकेंगे और जिस दिन मजदुरों के साथ यह वर्ग मिल जायेगा उसी दिन इस देश में क्रान्ति हो जायगी। आज हुकूमत ऐसी क्रान्ति को निमन्त्रण दे रही है। इसलिये मैं हुकूमत से यह दरख्वास्त करता हूं कि आप के द्वारा बैठाये गये कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको सारे हिन्दुस्तान के शिक्षकों पर एक तरह से लागू करना चाहिये और इसके लिये हुकूमत को कदम उठाना चाहिये।

इलाहाबाद में जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जो तनावपूर्ण स्थिति है, हमको बड़ा ताज्जुब होता है जब हम अखबारों में यह पढ़ते हैं कि प्रधान मन्त्री जी वहां गई तो और

[श्री रेवती कान्त सिंह]

तनाव बढ़ गया, उपमन्त्री जी गये तो और तनाव बढ़ गया । आखिर उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है । मैं जहां तक समझ पाया हूं या जो मुझे सूचना है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के नगरों के निगमों का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को दृष्टि में रख कर साम्प्रदायिक तत्व इ तरह से सिर उठा रहे हैं और इस तरह के साम्प्रदायिक दंगे कराये जा रहे हैं । इस तरह से मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि इन दंगों को रोकने के लिये कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय, कड़े से कड़े कदम उठाये जायं चाहे उसमें कोई भी आता हो । इन शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का यह बजट निराशा का बजट है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई आशा नहीं बंध सकती है, न उनकी औद्योगिक तरक्की हो सकती है, न खेती की तरक्की हो सकती है, न सिचाई की तरक्की हो सकती है न शिक्षा की तरक्की हो सकती है, न पब्लिक हैल्थ की तरक्की हो सकती है । इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. K. KUMARAN) in the Chair]

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो उत्तर प्रदेश का बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । इस बजट को मैं किसी दलगत दृष्टिकोण से देखना पसन्द नहीं करूंगा क्योंकि यह बजट ऐसे समय में इस सदन के सामने आया जब जनजीवन में गणतन्त्र के प्रति आस्था बढ़ने के बजाय घट रही है और जब देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि राजनीतिक मान्यताएं टटी जा रही हैं, जब रोज़ दल-बदल के कारण सरकारें अस्थिर हो रही है, कोई हट रही है, कोई बन रही हैं । ऐसी स्थिति जब देश और प्रदेश में आ गई तो उसके कारण इस केन्द्र की सरकार को राष्ट्रपति के शासन के संचालन के फलस्वरूप यह बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत करना पड़ा । इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रमों की सम्पूर्ति की रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ेगी । निश्चिय ही न इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रोग्रामों की बात होगी, न जनसंघ की होगी, न संसोपा की होगी और न कम्युनिस्ट पार्टी की होगी । इसलिए दलगत दृष्टिकोणों से इस पर दृष्टिपात किया जायगा तो किसी का प्रोग्राम नहीं पाया जायगा । मान्यवर, हमारे देश और प्रदेशों की आर्थिक व्यवस्था किसी सीमा से बंधी है । वह सीमा यह है कि पिछले 20 वर्षों में जो हमारे योजनाबद्ध कार्यक्रम हैं उनके लिए जो पहले से खर्चों को हमने स्वीकार कर लिया है, जो अपने ऊपर, समाज और प्रदेश के ऊपर व्यय-भार स्वीकार कर लिया है उसके कारण हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते और जब हम यह देखते हैं कि हम करों की सीमा को भी आगे नहीं बढ़ा सकते, उसकी आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं तो नए कार्यक्रम भी नहीं लिए जा सकते हैं । इसीलिए उत्तर प्रदेश के बजट में हम नए कार्यक्रमों को नहीं पा रहे हैं और पहले से चले हुए कार्यक्रमों में भी कमी देखते हैं तो निराशा अवश्य होती है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब स्थिति उस प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है ।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेष कर विरोधी दल के सदस्यों ने, इस सदन में फिर इस बात की चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू करना उचित और आवश्यक नहीं था । महोदय, मैं उन लोगों में हूं जो कभी यह पसन्द नहीं करते कि हमारे देश के किसी भी भाग में जहां गणतन्त्र की मान्यता हो वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाय । परन्तु आप जानते हैं कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति का शासन लागू करने की एक आपातिक स्थिति है और पिछले आम चुनाव में जो स्थिति हमारे देश में, विशेषकर

उत्तर भारत में आई कि एक के बाद एक प्रदेश में एक दल को हटा कर खिचड़ी सरकारें बनाने की चेष्टा की गई उसका स्वाभाविक परिणाम था कि कोई स्थायी सरकार किसी प्रदेश में नहीं बन पाई और यही कारण है कि पश्चिमी बंगाल में उसकी अस्थायी सरकार के हटन के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, यही कारण है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन हुआ और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा।

संविद के लोग सदन में और बाहर इस बात की बड़े जोर से चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उनका बहुमत है और उनका नेता चुन लिया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो संविद के घटक है उनमें दो सबसे बड़े जनसंघ और संसोपा है, जनसंघ के करीब 98 सदस्य है और संसोपा के करीब 44–45 सदस्य। जब कभी कोई कोलीशन या संयुक्त सरकार बने तो मुनासिब यह होना चाहिए कि सबसे बड़े देल का नेता मुख्य मन्त्री हो और पूरे तौर से शासन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, वह न हो तो उसमे छोटा दल ले। जब आप यह चाहेंगे कि आपका बहुमत डिफेक्शन्स से बने, दूसरे दलों से आए से बने और उन लोगों को आप बड़े बड़े ओहदे देंगे, प्रलोभन देगें तो पद और पैसे की लिप्सा देकर जो सरकारें बनाई जाएंगी वे न स्थायी शासन दे सकती है, न समाज को नैतिकता दे सकती हैं, न आर्थिक उन्नति दे सकती हैं और न किसी प्रकार जनजीवन में अच्छे भाव स्थापित कर सकती है। यही कारण है कि पिछले दस महीनों में समूचे उत्तर भारत में अव्यवस्था की स्थिति रही है बंगाल से लकर पंजाब तक जिसका उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा शिकार है और में कहूंगा कि यह जिम्मेदारी उन राजनीतिक दलों की है जिन्होंने पूरे तौर से अपने ऊपर इस देश के और प्रदेश के शासन की जिम्मेदारी लेने का अहसास नहीं किया था, कितनों के पास चुनाव में अपनी पार्टी के उतने उम्मीदवार नहीं थे जितने बहुमत के लिए आवश्यक थे। इसलिए उन्होंने पहले से नारे दिए, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने नारे दिए, जयप्रकाश जी और राजाजी ने कहा कि कांग्रेस को हटाया जाय और उसकी जगह संयुक्त मोर्चे की सरकार बने। जनता ऐसी मानसिक स्थिति मे पड़ी कि ठीक से फैसला नहीं कर सकी। यद्यपि इस देश के और सारे प्रदेशों के एक विशाल जनमत ने कांग्रेस को अधिक से अधिक संख्या में चुना, फिर भी उस अस्थिरता का नतीजा यह हुआ कि सारे उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल गई और उत्तर प्रदेश में जो संविद के घटक हैं उनमें अभी भी यह स्वीकार करने की क्षमता नहीं आई कि संविद सरकार के न चलने का कारण वे स्वयं हैं, उनके कार्यक्रम हैं। गणतांत्रिक सरकार का सबसे पहला और बुनियादी उसूल यह है कि जो संयुक्त सरकार बने उस में जो कार्यक्रम स्वीकार होगा वह सबकी रजामन्दी मे तो होगा ही, वह कार्यक्रम ऐसा होगा जिसको सब मिल कर पूरा कर सकें। उत्तर प्रदेश ने जितने दल थे उनके अलग अलग मन्त्री हुए और अलग अलग उनको महकमे मिले। मन्त्रि-परिषद् में भी बैठ कर एक राय से उन्होंने फैसला लिया हो यह बात सुनने में नहीं आई। बाहर आकर तो किसी ने मन्त्रिपरिषद के किसी फैसले का परिपालन नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि उनमें आपस में कशमकश रही और आज हम उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का अभाव देखते है, अशांति देखते है उपद्रव देखते हैं और सामाजिक जीवन में उथल-पुथल देखते हैं, निराशा देखते हैं, अविश्वास की भावना देखते हैं, शासन में गिराव देखते हैं, आर्थिक स्थिति में जो अवनति हो रही है, प्रदेश के रचनात्मक और तरक्की के कार्यक्रमों में जो कमी आ रही है उस सब का कारण संविद की सरकार है। और संविद सरकार के लोगों ने क्या किया ? जब वे शासन में बैठे तो उन्होंने अपना जो न्यूनतम कार्यक्रम

[श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल]

बनाया था उसके सम्बन्ध में मतभेद रहे--- मैं यह मानता हूं कि मिली जुली सरकारों का कार्यक्रम समझौता कार्यक्रम हो सकता है, परन्तु वह तभी हो सकता है जब सब अपने उन कार्यक्रमों को जिनके बारे में मतभेद है छोड़ दें और जिन पर एका है उनको चलाने की चेष्टा करें। हुआ क्या? जिसको उन्होंने मुख्य मन्त्री बनाया संसोपा की जो कृषि नीति है---जिसको एग्रेरियन पालिसी कहते हैं--- वे उसके खिलाफ थे। चुनांचे चौधरी चरण सिंह 6 एकड़ भूमि से लगान माफ करने के पक्ष में नहीं हुए और उनके जो भूमि सुधार के कार्यक्रम के उनको वे मानथे वाले नहीं थे। इस तरह पहली कठिनाई उनके सामने इसके इम्प्लीमेंटेशन की आई। राज्य कर्मचारियों के वेतन का मामला था, शिक्षकों के वेतन का मामला था, जिनका बहुत से सदस्यों ने जिक्र किया। इन बातों से उनकी सहमति नहीं थी, इनको वे स्वीकार करते वाले नहीं थे। खर्चे का जो भार था उसको पूरा करने का एक रास्ता था कि प्रदेश की जनता पर कर लगाया जाता लेकिन इन सब पार्टियों में यह साहस नहीं था कि प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त कर लगाते, वे जानते थे कि पूरे पांच वर्ष चला नहीं पाएंगे, मध्यावधि चुनाव के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए करों को माफ करवाओ, वाजिब कर माफ हुए---वाजिब कर माफ हुए या नहीं हुए यह बात नहीं थी, वे चाहते थे कि चीफ पापुलेरिटी मिले, जनता म उनकी लोकप्रियता बढ़े, इसलिए उन्होंने करों को माफ कराने की कोशिश की। चुनाचे उन्होंने बहुत से करों को माफ कराया। मान्यवर, यह तो राजनैतिक स्तर पर बात रही, किन्तु उस प्रदेश के सामाजिक जीवन में होड़ लग गई जनसंघ और संसोपा में कि अब कौन पार्टी अधिक बलवान हो जाय, अधिक मत लेकर कांग्रेस के बाद उस प्रदेश का शासन संभाले। इन दोनों दलों में, जो संविद् सरकार के मुख्य घटक थे उनमें इस बात की रस्साकसी शुरू हुई। जनसंघ के हाथ में वहां का गृह मंत्रालय था, पुलिस फोर्स थी, एक तरह से मुख्य प्रशासन उनके हाथ में था, तो इस रस्साकसी का नतीजा था, जनसंघ के शासन में जो नीतियां बर्ती गई उसी का परिणाम आज मेरठ और इलाहाबाद का साम्प्रदायिक दंगा है, आज शासन से हटने के बाद उन्होंने उसको उभारा है और संसोपा के लोग भी इस बात को देख रहे हैं कि जनमत में किस प्रकार से एक तनाव उत्पन्न किया जाय, एक झगड़े की स्थिति पैदा की जाय जिससे कि जनता उनकी ओर आकर्षित हो, और जनसंघ के लोग भी यही चाहते हैं, इसलिये उन बातों को उठाते हैं जिससे आपस में तनाव बढ़े और वह एक व्यक्ति नेतृत्व को ले सके। मेरठ और इलाहाबाद के झगड़ों के पीछे यह भावना है और जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि इनकी आंख आने वाले नगरपालिकाओं के चुनाव पर है, इलाहाबाद, लखनऊ और मेरठ के जो कार्पोरेशंस हैं इनके चुनावों में जनमत को अपने साथ करने के लिये यह सारा उपद्रव है और साथ ही उनकी दृष्टि आगे आने वाले मध्यावधि चुनांव पर भी है। वह जनमत को साथ करने के लिये ऐसी ही भावनाओं को जाग्रत करना आवश्यक समझते हैं जिससे कि जनता बिना विचार किये हुये उनके साथ आ सके। उनके पास कोई व्यावहारिक राजनैतिक कार्यक्रम नहीं है, आर्थिक कार्यक्रम भी नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं है जिससे कि जनता उनकी ओर आकृष्ट हो सके। शासन में 20 वर्ष तक रहने वाले कांग्रेस दल के दोषों को दिखाने और साम्प्रदायिक भावनाओं को उभाड़ने के अलावा उनके पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने

अपने को एक तरह से बेतहाशा उस दौड़ में छोड़ रखा है जैसे कि दो घोड़े सरपट रफ्तार से दौड़ते हैं और कुछ भी आगे आ जाय नहीं देखते, आगे दौड़ने में उनके पैरों के नीचे क्या चीज आती है इसको वह देखते नहीं, वह दायें बायें कुछ नहीं देख रहे हैं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो संविद है उसका दावा यह है कि वह उसका बहुमत है । (*Time bell ings*) मैं थोड़ा पांच मिनट का समय ही और लूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कल और परसों वहां राज्य सभा के और विधान परिषद् के चुनाव हैं, उनमें ही पहले उनकी परीक्षा हो जायगी कि उनके पास बहुमत है या नहीं । आज संविद की जनरल बाडी की मीटिंग भी बुलाई गई है । मायवर, मेरी यह चुनौती है । पहले भी मैंने कहा था कि संविद में एक घटक है रिपबलिकन पार्टी और उसका बहुमत उनके साथ नहीं है, पी० एस० पी० का बहुमत भी उनके साथ नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी, संसोपा और जनसंघ भी बंट गये हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो उनके साथ नहीं हैं । ऐसी स्थिति में उनके साथ बहुमत नहीं है । माननीय राजनारायण जी कहते हैं कि संविद का नियम यह है कि उनके नेता जिसको नामजद कर दें वही संविद का नेता मान लिया जाय इस तरह वह दल के उन लोगों का मुकाबला नहीं करना चाहते जो कि उनके खिलाफ हैं, वह चाहते हैं कि ऐसे ही उनके कह देने से नेता मान लिया जाय ।

महोदय, इस अवसर पर मैं उत्तरप्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व की सरहाना करना चाहुंगा पिछले लगभग एक साल से विधान सभा में बहुमत से हटने के साथ ही त्यागपत्र देना, उसके बाद विरोधी दल में बैठ कर के जिस अनुशासन, जिस डिगनिटी और जिस रचनात्मक भावना से विरोधी दल का कार्य उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने किया हैं उसके लियेवह सराहना की पात्र है । मैं यह चाहता हूं कि अन्यत्र जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वह इसका अनुसरण करना सीखें । जिम्मेदारी के साथ जो विरोधी पक्ष में बैठेगा वह इसी भावना से बैठेगा कि इंतजार कीजिये, प्रतीक्षा कीजिये, जब बहुमत बने तो अपनी सरकार बनाएं ।

मान्यवर, मैं इस समय यह भी कहना चाहूंगा कि दल-बदल और डिफेक्शन का हम चारों तरफ से शोर करते हैं, उसकी निन्दा करते हैं परन्तु यह नहीं सोचते कि कैसे यह बन्द हो । इसके बन्द होने का तरीका कानून से हो सकता था, उसकी परीक्षा हो रही है, किन्तु मैं नहीं समझता कि उसका क्या नतीजा निकलेगा । लेकिन मैं यह समझता हूं कि उसका सब से बड़ा उपाय यह है कि प्रत्येक दल और विशेषकर सब से बड़ा कांग्रेस-दल इस बात का संकल्प करे कि वह डिफेक्शन के द्वारा बहुमत बना कर सरकार नहीं बनायेगा । उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व के सामने यह समय परीक्षा का समय है । बहुमत में होते हुए भी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी, साल भर विरोध में बैठ कर जिस शान और जिस रचनात्मक और राजनीतिक बुद्धि का उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, मैं चाहूंगा कि उसको और भी वह परिपक्व करे और किसी भी तरह से पदों का प्रलोभन दे करके या पैसों का प्रलोभन दे कर के या किसी और प्रकार से अनुचित ढंग से वह सरकार न बनाये, यदि ऐसे लोग हों जो कि खुले आम इस बात का एलान करें कि उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में सुव्यवस्था और सुदृढ़ता लाने के लिये अपना यह राजनैतिक कर्तव्य समझ रखा है कि बिना किसी पद के प्रलोभन के कांग्रेस की सरकार का समर्थन करेंगे तब तो उनको साथ लेकर सरकार बनाने की चेष्टा करें अन्यथा किसी प्रकार से भी ऐसा काम न करें कि फिर कुछ ही दिन बाद हाथ से लोग

[श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल]

निकलें, यह तो मेंढक को तोलने वाली बात है कि मेंढक तोलना शुरू करते हैं तो कुछ तराजू से निकल कर भागते ही रहते हैं और तराजू कभी सम नहीं होता है । ऐसी स्थिति में डिफेक्शन को बन्द करने का तरीका यही है कि जो बड़ा दल है, जिसने 20 वर्ष तक शासन को करते हुए उसकी जिम्मेदारी निभाई है, उसके ऊपर कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जनता यदि बहुमत नहीं देती है तो उसको, जनता की, आज्ञा मान कर विरोध में बैठे और जिस प्रकार से अब तक जनता की सेवा करते आये है उसी तरह से कांग्रेस करती रहे । जो किसी तरह बहुमत बना कर गद्दियों पर बैठे हैं, वह हमने देखा, इस तरह वह फिर गद्दियों को संभालने की चेष्टा में ही लगे रहेंगे और फिर उनसे जनता का हित नहीं होगा, चाहे वह काग्रेस बैठे या कोई दूसरा दल बैठे, संविद के लोगों ने 10 महीने बैठ कर इस बात का प्रमाण दे दिया कि डिफेक्शंन के द्वारा सरकार बना कर रात दिन अपनी कुर्सियों को बचाने की चिन्ता में ही लगे रहे और न तो वह बची और शासन को ढहा दिया ।

तो, मान्यवर, ऐसी राजनैतिक स्थिति को दूर करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि डिफेक्शन द्वारा सरकारें न बने, इसकी प्रथा डाली जाय और इस प्रथा की पूर्ति के लिये कांग्रेस के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश कांग्रस के नेतृत्व पर और केन्द्र के नेतृत्व पर जिम्मेदारी आती है । मै अपनी अकेली आवाज़ को उठाता हूं, यह मेरी अपनी आवाज़ है और एकदम अकेली आवाज़ है, जो शासन में आने के उत्सुक कांग्रेस दल के या दूसरे दल के लोग हैं वे शायद इसको स्वीकार न करें किन्तु यह प्रदेश के और देश के भावी जन-जीवन की राजनीतिक जीवनकी सुदृढ़ता के लिये, उसमें सुव्यवस्था लाने के लिये आवश्यक है । इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : माननीय वाइसचेयरमैन महोदय, यद्यपि यह उत्तर प्रदेश का बजट असन्तोषप्रद है तो भी मैं इसका समर्थन करता हूं । मैं इसलिये असन्तोषप्रद कह रहा हूं कि जितना उत्तर प्रदेश विशाल है, जनसंख्या के खयाल से वह हमारे हिन्दुस्तान में अव्वल है और अभी 8 करोड़ से ज्यादा उसकी आबादी हो गई है, उस के हिसाब से यह रकम कुछ नहीं है और खास करके जो उसके पूर्वी क्षेत्र हैं वे इतने पिछड़े हुए हैं कि उसकी तरक्की के लिये, उसके विकास के लिये जितना भारत सरकार को पैसा देना चाहिये उतना पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है । कानपुर को छोड़ कर जहां कल-कारखानों और उद्योगों का सवाल है पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है । इसकी बदकिस्मती कहिये या इस का सौभाग्य कहिये कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वह वहीं से होते है और प्राइम मिनिस्टर यह सोचते हैं कि यदि हम अपने प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें तो लोग क्या कहेंगे, यद्यपि न्याय तो यह कहता है कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा आबादी हो उसको प्लानिंग के लिये योजना के लिये ज्यादा पैसा मिलना चाहिये लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि बराबर वहां से, यू० पी० से प्राइम मिनिस्टर होने से यह नज़रिया होता है कि वह प्राइम मिनिस्टर तो देता है लेकिन रुपया कम मिलता है, इसलिये ही वह कोशिश नहीं करते कि ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर उत्तर प्रदेश का विकास करें । अभी भी हमारे पंत जी हो गये वित्त मंत्री तो इन्हें भी झिझक लगेगी । हैं तो राज्य वित्त मंत्री लेकिन यह भी झिझक जायेंगे, सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश को नहीं मिलना चाहिये । पुरानी आदत जैसी हो गई है । पहले नेहरू जी को, फिर लाल बहादुर जी को और अब श्रीमती इन्दिरा गांधी को ।

हमको याद है कि जब हमारे माननीय श्रद्धेय गोविन्द बल्लभ पत जी होम मिनिस्टर थे और जब मैं पूर्वांचल की यूनियन टेरीटरीज के लिये लडता था, मणिपुर और त्रिपुरा के लिये, तो कहते थे कि त्रिपुरा की आबादी ज्यादा है, खाने वाले ज्यादा हैं इसलिये हम ज्यादा देते है। तो हमारा कुछ हिसाब किताब ऐसा है कि जहा आबादी ज्यादा बढ रही है वहा वैसा देते है लेकिन उत्तर प्रदेश को ज्यादा नही मिलता । हमने उनको मजाक मे कहा था कि क्या मणिपुर की आबादी कम है तो ज्यादा पाने के लिये क्या हम आह्वान करे कि वहा फेमिली प्लानिग बन्द करके ज्यादा से ज्यादा लडके लडकिया पैदा किये जाये, जिससे ज्यादा पैसा मिले । कहने लगे नही मेरे कहने का मतलब यह नही । एक यही नही कि उत्तर प्रदेश से हमारे प्राइम मिनिस्टर आते है लेकिन आप अतीत काल से देखिये जब से दुनिया शुरू हुई, सारी सभ्यता, गगा जमुना, वही से निकली है । इसलिये शिक्षा के खयाल से, धार्मिक स्थान के खयाल से यू० पी० का दर्जा अव्वल रहा है, लेकिन बदकिस्मती है कि योजना मे, विकास मे और प्लानिग मे यह बहुत पिछडा हुआ है इसलिये भारत सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा रुपये की सहायता करे क्योकि जब तक वहा का विकास नही होगा, कल कारखाने नही लगेंगे, छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज नही लगगी तब तक यहा खुशहाली नही होगी क्योकि 8 करोड से ज्यादा उसकी आबादी हो गई है, और उससे वहा बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई है । कम से कम एक चीज तो वहा है कि अन-इम्प्लायमेंट की फेक्टरी जो युनिवर्सिटीज है वह सब से ज्यादा यू० पी० मे है और वहा से बहुत सारे निकल रहे है और यदि यू० पी० का उद्योग विकसित होगा तो उनके लिये गुजायश रह जायेगी । इसलिये मै इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा हू कि सारे यू० पी० का औद्योगीकरण तो होना ही चाहिये लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वह बहुत बैकवर्ड है जहां से हमारे नारकेश्वर पाडे जी आते है और जो हिस्सा हमारे बिहार प्रदेश के साथ भी पडता है । इसलिये यह जरूरी है कि उसका विकास किया जाय ।

यू० पी० मे सब से ज्यादा शुगर फैक्टरीज है और शुगरकेन सेस लेकर पैसा भी काफी इकट्ठा होता है लेकिन वह पैसा कहा जमा हो जाता है । उसमे से जो मिलता है वह किसान जो शुगरकेन पैदा करते है, उनकी भलाई के लिये और शुगरकेन के डेवलपमेंट के लिये मिलना चाहिये । जहाँ जहाँ शुगर फैक्टरीज है वहा जाने के लिये जो सड़कें होती है उन पर वह खर्च होना चाहिये । लेकिन वह हो नही पाता है सडको का डेव-लपमेंट नही होता है । इसलिये शुगरकेन कल्टीवेशन वाले एरिया का भी डवलपमेंट नही होता है । जब तक शुगरकेन का प्राडाक्शन और डेवलपमेंट नही होगा तबतक ज्यादा से ज्यादा शुगर फेक्टरीज कैसे रहेगी । महाराष्ट्र में और सभी प्रान्तों मे जिस तरह से शुगरकेन का डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से वहा के यील्ड मे बढोत्तरी हुई है । उत्तर प्रदेश और बिहार मे चूकि हम शुगरकेन का डवलपमेंट नही कर रहे है इसलिये उसका कारोबार ठीक नही चल रहा है और ठीक से बीज और सीड नही मिल रहा है इस से गड़बड़ होती है । इसलिये कोशिश यह होनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा शुगर-फेक्टरीज वहा पर बने । क्यो नही शुगर केन का विकास होता है और इस तरह की परिस्थिति क्यो हो गई है ।

तीसरी बात, यह बदकिस्मती है कि य० पी० और बिहार का सीमा विवाद का प्रश्न अभी तक नही सुलझ

[श्री शील भद्र याजी]

पाया है जो कि गगा के कटाव की वजह से पैदा हुआ है। कभी प्राइम मिनिस्टर के यहां तक मामला जाता है कभी दूसरी जगह। इतना झगड़ा माननीय व्हाइस चैयरमैन साहब हो रहा है और इतने लोगो की, किसानों की जान जाती है जमीन की बोवाई के वक्त मे, फसल काटने के वक्त मे और बराबर इस का झगड़ा हो रहा है और भारत सरकार कभी प्राइम मिनिस्टर को दिया करती है कभी उधर दिया करती है, विधेयक भी आता है लेकिन संतोषजनक हल नहीं हो पाया है। इसलिये यह भारत सरकार के लिये मुनासिब था कि इस पर कोई निर्णय देती खास कर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगो की जान जा रही है हर साल। फिर भी इस मामले में ढिलाई हो रही है। उसमे हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ फैसला कर देना चाहिये। यदि कुछ भाग बिहार मे या उत्तर प्रदेश मे चला जाता है, तो यह कही बाहर तो नही जाता है, वे आफ बंगाल या अरेबियन सागर मे तो नही चला जाता है। तो हिम्मत और दिलेरी के साथ इसका जो फैसला होना चाहिये, वह नही हो रहा है और इसलिये जो किसान बेचारे हैं, जो खेती करने वाले है, दोनो तरफ उत्तर प्रदेश मे और बिहार मे उनकी जान जाती है, फौजदारी होती है, रायटिंग होता है। यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है।

अन्त मे मै एक बात और कह कर सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हुं। एक चीज की ओर इशारा हमारे विरोधी दल ने भी किया और शुक्ल जी ने भी किया। जो यह बजट हम यहां पास कर रहे है इस पार्लियामेट मे इसको उत्तर प्रदेश की विधान सभा मे पास होना चाहिये था, लेकिन हमको इसकी शुरूआत मे जाना चाहिये। लेक्चर तो हम सब लोग सुनते रहते है, सब लोग उपदेश देते है। लेकिन लैक्चर के भुक्तभोगी हम हो रहे है, राजनारायण जी रोज लेक्चर देते है, भूपेश गुप्त भी लेक्चर देते है, जगजीवन बाबू पर इशारा करके लेक्चर देते है कि आप चरण सिह की तरह डिफैक्ट कर दीजिये, प्रधान मत्री बना देगे, कोई शरम नही आई उनको ऐसा कहने मे, लेक्चर देते है लेकिन शुरूआत वही कराते है। गुप्ता जी की सरकार को उलट दिया और हमारे आदमी चरण सिह बाबू जैसे सीजन्ड आदमी को लेकर शुरुआत हुई, तो यह डिफेक्शन की जो बीमारी हो गई . . .

एक माननीय सदस्य : वह पहले किसने करवाया ?

श्री शीलभद्र याजी : वह पहले हमने नही किया। हमने पहले कहा था कि हम कोई साधु समाज की जमात नही है, हम भी जैसे को तैसा, टिट फार टैट करेगे। लेक्चर मत दीजिये। आप लेक्चर देने के पहले दिल को टटोलिये, किसने पहले शुरू किया। हमने कहा अगर आप करेगे तो बुरी तरह से मार खायेगे। मे नही कहना चाहता था लेकिन पहले आपने चरण सिह को डिफेक्ट करा के गवर्नमेंट को उल्टा, फिर हरियाना मे राव वीरेन्द्र राव को किया और सरकार को उल्टा और फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र के साथ वही किया, वहा की सरकार को उल्ट दिया, तो क्या आप समझते है, हम चुपचाप देखते रहेगे। अभी भी आप वही करते है। यह कोई शोभा की बात नही है।

यह ठीक है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को अज्ञान बुद्धि आ रही है। अभी हमारे विरोधी दल के साथी बोले कि जनता की सरकार, तो क्या जनता की सरकार कांग्रेस को रेप्रेजेन्ट नहीं करेगी, तो क्या वह जनसंघ को करेगी, स्वतन्त्र पार्टी को करेगी, जिनके साथ वह खुद गठबन्धन करते हैं। मैं कहता हूं वह जनता की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार होगी, यह सबको सोचना चाहिये, विचारना चाहिये। बोलने के लिये तो आपको आजादी है। कल बोलते बोलते हमारे भूपेश गुप्त जी, तमाम जितने शब्द, एड्जेक्टिव डिक्शनरी के हैं कह गये, हमसे कहते हैं चौदह पार्टिया छोड गये। उन्हें पता नहीं हम कांग्रेस में पैदा हुए। कांग्रेस मैंने नहीं छोडी, जब मैं फारवर्ड ब्लाक में था, तब फारवर्ड ब्लाक भी विदिन दी कांग्रेस पार्टी एक सोशलिस्ट पार्टी की हैसियत से था। तो कहने की आजादी है, इसलिये उन्होंने कह दिया। तो मैं कह रहा था कि यह बजट उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पास होना चाहिये था, लेकिन यदि नहीं हुआ तो इसका श्रेय हम लोगों के ऊपर नहीं है, आप लोगों का है। भविष्य में भी यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की परिस्थिति नहीं हो रिएक्शनरी, प्रतिक्रियागामी, साम्प्रदायिक तत्व यह जो स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ पार्टी के लोग हैं, उनको छोडकर जो अपने को समाजवादी कहते हैं, वह हमारे साथ आएं। उन पार्टियों से गठबन्धन करने से पहले शरम आनी चाहिये। जितनी डिमाक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टिया हैं वह कांग्रेस में आएं। अगर जनसंघ या स्वतन्त्र या रिएक्शनरी लोगों का आप साथ देंगे, तो समाजवाद की स्थापना नहीं होगी। एक और चीज की मैं चेतावनी देता हूं विरोधियों को कि यदि कांग्रेस कमजोर हुई तो समाजवाद भी नहीं आयेगा और देश की बुरी हालत होगी। इसलिए डिफेक्शन्स मत करवाइये और कांग्रेस का जो समाजवादी प्रोग्राम है, उसमें कांग्रेस का आप सहयोग दीजिये, इसी में आपका कल्याण है, देश का कल्याण है, सब पार्टियों का कल्याण है, इन शब्दों के साथ फिर मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का राज्य इतना महान है, बडा है कि जितना रुपया प्लानिंग के लिये योजना के लिये दें, वह कम है। इसमें जो रुपया दिया गया है बहुत कम है, असंतोषप्रद है, लेकिन तो भी आधे दिल से मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the history of U.P. has been very closely linked with the history of this country. U.P. has had the proud privilege of giving all the Prime Ministers to the country so far. For U.P. that is a very good thing. But personally I feel that because we have supplied Prime Ministers to this country we have suffered economically. Whenever we have wanted more money for our Plans we have been told Well, you have the Prime Minister. Why do you want money? I have no hesitation in saying that U.P. today is at least one Plan backward in all its spheres of development whether it is agriculture, whether it is irrigation small or major, whether it is health, whether it is education. In all respects, if we analyse the figures of the various States we will find that U.P. is one Plan backward.

1 P.M.

Now we will have to go back a little to find out why the necessity arose for discussing the U.P. Budget here. As I said a little earlier, the history of U.P. has been connected with the history of the country. In the 1952 elections, U.P could send only 14 Members of the Opposition, most of them Independents, out of the 420 members elected to the U.P. Assembly. That was the strength with which U.P. began. And Uttar

[Shri M. P. Bhargava]

Pradesh was fortunate in having a Chief Minister of the stature of Pandit Govind Ballabh Pant at that time. I have no hesitation in saying that he had been one of the ablest parliamentarians the country has produced after independence. And when Pantji was called upon to shoulder responsibility at the Centre, I was both happy and sad. I was happy because an able administrator was coming to the Centre and he would be useful to the Centre and the country as a whole would benefit. I was sorry because Uttar Pradesh was going to lose a Chief Minister who was head and shoulders above all his colleagues. It was even said that in Uttar Pradesh, there was only one Minister and that was the Chief Minister, Pandit Govind Ballabh Pant; and the others were a team who used to help him and act according to his wishes. So in the beginning of 1955 when he came here, a giant was removed from the U.P. political scene. And when a giant is removed from any scene, difficulties arise. And that is exactly what happened in Uttar Pradesh. Difficulties arose. The result was that in 1957, the strength of the Opposition which was only 44 in 1952, swelled to 144 because of the difficulties experienced by the removal of the giant called Pandit Govind Ballabh Pant. Things began to move and began to take shape. Then came the 1962 elections. Things deteriorated and the Opposition further increased its strength and it went up to over 160 in a House of 425.

After the 1962 elections, the country had a severe blow in May 1964 when Pandit Jawaharlal Nehru, our first late lamented Prime Minister, who put the country on the map of the world, passed away. And then a curious procedure began. Normally it is expected that the Centre will guide the States; and that should be the correct procedure. But in 1964, the gear was put in the backward direction. What I am referring to is that instead of the Centre or the Congress Parliamentary Party electing its leader, the State Chief Ministers and others asserted themselves and tried to show that they were chosing the Prime Minister. It was good at that particular time that it was the party's choice that Shri Lal Bahadur Shastri be elected leader, and it became the choice of the Chief Ministers of the various States also that he be elected leader. And so without any difficulty, he was elected unanimously. But the forces which came up at that time began to assert themselves. The Chief Ministers began to want their pound of flesh in the Central Ministry. They wanted to dictate, they began to dictate terms to the Centre. And the Centre began to become weak. Shri Lal Bahadur Shastri, our second respected Prime Minister, began rather weak, began rather shakily, but by his honest and hard work, by his keen desire to develop the country, by this sincerity of purpose, by his courage of conviction, by his persuasive methods and by his method of working, soon got a grip over the situation. By the time the Indo Pakistan conflict came, he had become the supreme leader of the country. Small as he was, people doubted whether that small man would be able to govern such a big country. But he soon showed that he had all the capacity which is required of a practical leader. He led the country to a successful and useful war against Pakistan. Then came the time for him to show that he was not only a war time leader but he was a peace-time leader also. He went to Tashkent and what he did there is very well known to the hon. Members of this House. He showed that if he was a war-time leader, he could be

a peace time leader as well. And it is one of the rare things in world history that his dead body was carried by his opponents on their shoulders. You will not find a parallel to it in history. With the death of Shri Lal Bahadur Shastri, the forces which had started showing their faces in 1964, again came to the fore and they asserted that it is their right to elect a new leader. And they elected the present Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. In fairness to her, I must say that she has been carrying on the burden of Prime Ministership in a most dignified, graceful manner. The country has every reason to be proud of having her as the Prime Minister. But I am sorry to say that she is not having the correct counsel and some people around her are not behaving as they should. And that is creating complications not only for her but for the country also. With this situation we went to the polls in 1967. I will not go into the other things. I will only quote what happened in U.P. In U.P. out of 425 seats at that time the Congress got 199, Swatantra 12, Jan Sangh 98, SSP 44, CPI 13, CPI (M) 1, PSP 11, Republican 10 and Independents 37. It was in the fitness of things that the Leader of the Congress Legislature Party, Shri Chandra Bhan Gupta, was invited to form the Government. Here I want to pay my tributes to this gentleman. He is the one leader in India who has shown that he is a democrat and a democrat right through. When he lost in a division, he did not hesitate for a minute to announce in the Legislature itself that he would no longer be the Chief Minister and he shall resign forthwith. That is what is expected if we have to play the game of democracy fairly, smoothly and well. And I would have expected that all through the country his example would be followed and people would not hesitate if they are defeated and they would go out. After Shri Chandra Bhan Gupta's resignation a vacuum arose and efforts had to be made to find a Ministry which could be stable. Now I am reminded at this stage of a well-known Hindi saying:

कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा,
भान मत्ती ने कुनबा जोड़ा।

And that is exactly what happened in U.P. -divergent forces representing the so called right ideas, divergent forces representing what are termed as left ideas. Parties which do not follow either the right or the left line of thinking they all came together and said "We will form what is called the SVD." Although there were 7 constituents of that SVD, they could not find a leader from among themselves. Then the search for a leader began and they found a leader in the Congress defector, Shri Charan Singh. I had very high regard for Shri Charan Singh. I have known him for nearly two decades. I had always regarded him as a man of integrity and honesty and one who could be relied upon for any kind of responsibility. But my faith in the gentleman was badly shaken when he agreed to become the leader of the SVD. My estimation of the gentleman would have gone up if he had gone out of the Congress, resigned from the Assembly and sought re-election on the SVD ticket. That would have been a correct thing to do. But he did not choose to do that and as soon as he became the Chief Minister, the forces around him began to assert and he gradually began to feel that he was a misfit in the company he was keeping, because day in and day out, whether in the Cabinet or outside, he had to face peculiar situations, he had to reconcile varying views, he had to act according to what was called the minimum programme. Now what minimum programme can there be when people from

[Shri M. P. Bhargava.]

different parties sit together and say "We shall work democracy just to keep the Congress out, that is our only common point and that is only where we meet, on the remaining things we do not agree". And it was a beautiful situation that national parties in India held a certain view with regard to certain matters and the constituents of those parties in U.P. had to take a different view. With that kind of approach it was a foregone conclusion that the chiefministership of Shri Charan Singh would not be a lasting affair. Then again Shri Rajnarain, who is a pandit of all the rules of procedure, who thinks he is the wisest person alive on earth who can dictate to everybody as he likes and when he likes, took the stand that Mr. Charan Singh must go out of the leadership. And he succeeded. Mr. Charan Singh was forced to resign the leadership of the SVD. That is what has brought the present stage when we are discussing the State Budget. He wrote a letter to the Governor "I cease to be the leader of the SVD, another leader will be chosen. If another leader is available, you call him and ask him to form the Government. If that does not happen, then I recommend that the Assembly be dissolved and mid-term poll be held." The Governor waited for 9 days to see if the SVD could elect its new leader. Now the normal procedure for the election of a leader is that all the members who call themselves as the members of the SVD meet and elect a person who would be their leader. Obviously the SVD was not in a position to follow that procedure, because they knew that if a general body meeting was called, every constituent would put forward its claims and instead of electing a new leader, the whole SVD would go to pieces. That was the fear which held them back from calling a general body meeting of the SVD They adopted a noval procedure—a co-ordinating committee of the various constituents to elect their leader. They wanted a short-cut to leadership, because the other path was full of danger. They thought if they treaded the other path, they would go to pieces. So the S.V.D. could not elect a leader. At one stage a peculiar situation arose. Some sections of the S.V.D. said : "Mr. Charan Singh continues to be our leader and please call him back to form a Government" and the other sections said: 'Mr. R.C. Vikal, who was the original leader before Mr. Charan Singh became the leader, continues to be the leader. 'It is a thing unheard of in parliamentary democracy. Over and above this, Shri Rajnarain, who was responsible for breaking the S.V.D. has the courage to say here that the Governor has bungled in not calling the leader of the S.V.D. Mr. R.C. Vikal. If Mr. Rajnarain's stand is correct, why have they failed until to-day to elect a leader and it is only to-day I hear that the general body is holding its session to elect a leader or if I may put it in other words to ratify what the Co-ordinating Committee has done. I have my doubts whether the general body of the S.V.D. will be able to ratify the decision. That is the unfortunate state in which my State, which had the honour of leading this country for over three decades, is placed at the moment and that is how the Budget has come before us.

I have already said that U.P. is at least one plan backward as far as everything is concerned. Therefore, obviously, I am not in a position to say that the Budget is to my satisfaction. Beyond that I do not want to say anything.

SHRI K. C. PANT: Mr. Vice-Chairman, I have listened to the debate

with great attention and I propose to concentrate on those points which are of general interest and which have a direct bearing on the Budget. Many of the speeches which have been made contained constructive suggestions for the development of U.P. and for promoting its economic growth. I refer in particular to the speech of my friend Pandit Tankha. These suggestions will be taken note of not only by us here but by the officers of the U. P. Government who are here.

Before I turn to the Budget itself, may I make it absolutely clear to my friend Shri Sinha that the Centre did not have any particular desire to bring forward this Budget here. A certain situation was created in U. P. which left the President with no choice but to suspend the Assembly and under those circumstances, it has fallen on the Parliament to pass this Budget. I would refresh his memory because he seemed to suggest that it was not really necessary to have brought forward the Budget at this juncture and that it was avoidable, I would refer only to one statement by the erstwhile Chief Minister, Shri Charan Singh, himself who, according to a Press statement in National Herald, dated 13-1-1968, confesse :

> "The S.V.D. Government was suffering from the fatal disease of cancer and that it would wither away tomorrow, if not to-day. The Chief Minister stated that he was convinced that the S.V.D. Government was bound to fall sooner or later."

Then I would remind him that when the Governor sent his report to the President, he referred in that report to the fact that the S.V.D. had elected one leader in the morning of 21st February 1968 I am quoting from the Governor's report :

> "The very fact that the S.V.D. elected one leader on the morning of 21st February and had to cancel that election in the afternoon and elect another leader was indicative of the stresses and strains under which the Dal was functioning."

I continue to quote :

> "I also note that while in their earlier letter of 21st February 1968 the S.V.D. had stated that Shri Charan Singh had been elected unanimously as the Leader, in the latter leter of the same date signed by Shri Ram Prakash it was not stated that Shri Ramchandra Vikal had been elected unanimously and all that was said was that he had been elected without opposition."

Therefore it would be obvious that the Centre was not interested in bringing down that Government at all and after the President took the step, the leaders of the various political parties gave their reactions to that step. The Swatantra and the P.S.P. termed it as 'an inevitable step'. There was Shri Harish Chandra Singh, who was the former State Minister for Justice and Information and around whom the S.V.D. is now trying to form again and elect him as the unanimous leader. According to the Press reports, his comment while describing the President's Rule was that it was 'a logical and wise step' and he held the Jan Sangh responsible for wrecking the S.V.D. He also charged that the Jan Sangh had nominated their party members on the various Government sub-committees. Just to put the record straight, I would also quote that the Deputy Chief Minister, Shri Ram Prakash Singh (Jan Sangh) said that the crisis was essentially an outcome of the differences among the B.K.D., the S.S.P. and the Communists. Therefore it is obvious that what led to the downfall of

[Shri K. C. Pant.]

the U.P. Government were their inner contradictions, the fact that they could not pull on together and by no stretch of imagination could it be ascribed to any act of omission or commission on the part of the Central Government.

There was a reference by various Members to the need for development in U.P. and I dare say that I have sympathy with those who pleaded for a more rapid development in U.P. so that it can catch up with the other parts of the country in those areas, where it has fallen back but that is possible only in an atmosphere of political stability. It is only possible with a stable and stronger Government, with an impartial administration and these are the pre-requisites that are required in U.P. to-day. I hope the House will join me in wishing that all these things do come about in U. P. quickly and that U.P. can again enjoy the blessings of a stable Government which it has been deprived of unfortunately during the past so many months.

Coming to the reference to the last 15 years' growth and development, I would refer Members to the Plan outlays and Central assistance since the First Plan. In the First Plan, Central assistance to U.P. was Rs. 87 crores out of a total plan outlay of Rs. 166 crores—which comes to 52·4 per cent in the Second Plan it came to 53·1 per-cent. In the Third Plan it was bigger; it was 65·4 per cent out of the total plan outlay of Rs. 513 crores. Thus it was a rise from 52·4 per cent in the First Plan to 65·4 per cent in the Third Plan. There has been a fall in the subsequent two years because of the condition of drought and the condition of scarcity of resources—which are well known to this House. In 1966-67 the percentage of Central assistance was 61·5 per cent. In 1967-68 it was 56·1 per cent; but the Plan outlay was slightly larger in 1967-68 at Rs. 156·04 crores.

The *per capita* plan outlay and Central assistance figures are also revealing. Central assistance, *per capita*, is Rs. 14 in the First Plan, Rs. 18 in the Second Plan, and Rs. 46 in the Third Plan. After that it has dropped sharply, to Rs. 11 in 1966-67 and Rs. 11 in 1967-68. But the all-India *per capita* Central assistance has also dropped in the last two years. It was 55 in the Third Plan as against 46 for U.P. It dropped to 12 in 1967-68 against which U.P's is 11. This is the picture of Central assistance and Plan outlay during the First, Second and Third Plans.

Now coming to the plan outlay in this Budget, the Plan outlay has been restricted to the resources in sight, and the figures are as follows: Rs. 161·7 crores for 1967-68 and Rs. 154·79 crores for 1968-69, including the Centrally sponsored schemes. Now the decrease in outlay is mainly on account of lesser provision for loans for agricultural purposes, but I would like to assure hon. Members that this has not been done without taking into account the needs of the farmer. As a matter of fact, the overall investment in the agricultural sector would not be affected because of the expanding rural credit programme by the co-operative sector as well as the credit likely to be advanced by the scheduled banks— I think my hon. friend Shri Tonkha. referred to this fact during his speech. The Land Mortgage Bank will extend its activities to 41 districts as against 25 districts this year, and they would be issuing debentures of Rs. 21 crores next year. And assistance would also be available through the Agricultural Refinance Corporation. The Agro-Industries Corporation which has been set up is also expected

to distribute pumping sets of the value of Rs. 4 crores in the Budget year for helping minor irrigation programmes. In fact, the total availability of funds for minor irrigation, about which hon. Members were naturally concerned, would be higher by Rs. 10·85 crores next year. While during 1967-68 a sum of Rs. 26·51 crores is likely to be mobilised for this purpose, it is proposed to arrange for total funds of Rs. 37·36 crores during the Budget year—that is the increase.

Then, Sir, various Members referred to the fact that U.P. was predominantly an agricultural State and that we should concentrate on doing whatever we can for stepping up agricultural production, particularly through the high-yielding programme. I have been to various districts of U.P. in the last few months and, Sir, it is a sight to warm one's heart to see the crop that has come up this year in the *rabi* season. I went to Eastern U.P. and I found that in those districts which were traditionally only rice-producing, this year there is a standing wheat crop which would compare any day with the crop in Western U.P. which is traditionally a wheat-growing area, and I have found that there is hardly one inch of cultivable land which has been left fallow. This I have seen with my own eyes and—as I said—it is something that encourages one, something that enthuses one, and so this year U.P. will have perhaps record production. About 5 million acres have been brought under the high-yielding programme—both of *Kharif* and *rabi* crops—and the target next year is 7 million acres, an additional production potential of 16·35 lakh tons would be created next year including 12·27 lakh tonnes under the high-yielding programme. In spite of the reduction in the Plan size the provision for roads in next year's State Plan has been stepped up.

Now, Sir, I come to the point made by various Members regarding the need to assist Eastern U.P., and various Members referred to the Patel Commission, and the report of a team that was submitted in January, 1961, and wanted to know what had been done about that. Now I would like to only briefly tell them that an outlay of Rs. 4·17 crores to be supported by Central assistance of Rs. 4 crores was approved for the year 1964-65. Along with the finalisation of the State's Annual Plan for 1965-66 an accelerated development programme of Rs. 4·5 crores for these four eastern districts, namely Ghazipur, Azamgarh, Deoria and Jaunpur, was approved to be financed by additional Central assistance of an equal amount. Thus a total of Rs. 8·5 crores was given to the State Government by way of special Central assistance for the programme in these four districts of Eastern U.P. Thus special assistance was provided for the accelerated development of the backward districts in Eastern U.P. during the years 1964-65 and 1965-66. I may add that two other districts were later included in the Eastern U.P. districts, which were eligible for special assistance after the visit of Shri T. T. Krishnamachari, ex-Finance Minister, to U.P.

Sir, now we have to see how much can be done during the Fourth Plan, and I hope that with resource mobilisation by U.P. and by the Centre it will be possible to do as much as possible, and I would at this stage be able to tell only this much to my hon. friends who are particularly interested in this problem, namely, that the requirements of specially backward regions will be taken into account while determining the overall Central assistance for the States' Annual Plans, and this would include U.P. So far as the outlays provided in the State's Plans

[Shri K. C. Pant.]

during the year 1967-68 and 1968-69 for these districts are concerned, they were for the year 1967-68, as anticipated, Rs. 13·97 crores, and for 1968-69 Rs. 14·06 crores.

Now, Sir, I come to a few points on which hon. Members wanted elucidation or information. My hon. friend Shri Yajee referred to the boundary dispute between U.P. and Bihar. I hope he knows that the Trivedi Award was received and considered and ultimately U.P. and Bihar agreed to that Award. A Bill has been passed by the Lok Sabha and I believe it is either pending before the Rajya Sabha or it has to be introduced here. I do not know the exact position now. Anyway, it is before Parliament and it has been passed by the Lok Sabha. And moreover, it does not really matter whether this portion is with U.P. or with Bihar. It is not going out of the country.

My hon. friend also referred to education and said that education in the State needed to be boosted and that the expenditure on Education needed to be increased. My hon. friend Mr. Menon also referred to it as also Mr. Mandal. I may say that the provision for Education has actually gone up. In 1966-67 it was Rs. 46·58 crores and the revised figure for the year is Rs. 52·07 crores and in the Budget for 1968-69 it is Rs. 58·35 crores. Then the point was made that the Kothari Commission's recommendations were not implemented in the case of the teachers in U.P. I would like to refer these hon. Members to the Budget papers and to say that Rs. 1·82 crores have been added to the next year's Budget provision as a result of the implementation of the Kothari Commission's recommendations in respect of the degree colleges. And party in D.A. with State Government employees has been given to the Higher Secondary School teachers and this has resulted in an additional expenditure of Rs. 1·77 crores. My hon. friends Pandit Tonkha and Shri Sinha referred to this point.

Then some hon. Members made the point that extra expenditure was being incurred on jails and police. Much was made of this. My reply would be if my hon. friends would cooperate with us perhaps it would be possible to consider reducing the expenditure on police. But in any case the expenditure on police has increased mainly due to the increase in the rates of dearness allowance and the transfer of the provision from Civil Defence Budget to this head. Therefore I do not know if they will take up the position that it was wrong to give this dearness allowance. If this dearness allowance is given then the expenditure is bound to go up. Similarly in the matter of jails although the increase is not much that is also due to the increase in the rates of dearness allowance. These are the main reasons for the increase in the Budget for jails and police.

Then I come to the point raised by Shri Mandal who referred to the plight of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I am in full sympathy with him. I would only add that the sympathy which he has for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes should also have inspired the decisions and activities of the Government to which his own party was a party in U.P. in the course of the nine or ten months that the S.V.D Government was there in the State. I personally heard some complaints in my own constituency and elsewhere that the grants etc. which were normally paid to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students had not been paid last year. Therefore while appreciating his sentiments I wish his

sentiments would become effective where his party was in power.

Then I refer to a point made by Mr. Mandal that land revenue has gone up by Rs. 3 crores and he made the point that this has gone up because land revenue had been extended to unprofitable agriculture. I may state that land revenue has not been extended. It so happened that last year due to difficulties –last year was a particularly difficult year for agriculturists—in many cases land revenue recovery was waived. But this year land revenue recovery is made every where because the crops are good. So also the consolidation dues are also fully recovered. These also had been waived last year. So on account of all these reasons last year the land revenue recovery had been suspended and all this is being recovered next year. Therefore the figures are higher now than last year. It is not because of extension of the scope of the land revenue provision.

My hon. friend also complained that land revenue had not been abolished. For that I think he should criticise his own party. His party was in the Government and in spite of this being one of their 10 or 52 point programme —they are still undecided about the number of elements or points in their programme—whatever the number may be, this was in particular one of their points, they could not implement it in the course of so many months when they were in power. And now it is rather unfair to expect the Governor within the short time that he had before him to implement what his own party's Government could not implement during the long period that they were in power. We hope that a stable Government would emerge in U.P. and all the necessary measures would be considered.

Finally I would like to associate myself with the sentiments that Shri Balachandra Menon expressed when he referred to the fact that communalism was rearing its ugly head in various parts of the country including certain parts of U.P. On this matter there can be no difference of opinion. We are all wedded to secularism and it is one of the basic pillars on which we want to build up this country and it is a principle on which we are all one, on which we are all agreed and united. It is unfortunate that in the recent past there have been instances of communal trouble and it is up to us, workers in different parties and different Governments, it is up to all of us, all right-thinking citizens, to take heed of the deterioration that has set in in the recent past and to set our face against it and to fight it and to see that in future this kind of thing does not recur and the trouble that is visible in certain places does not acquire a pattern but is nipped in the bud.

I think I have dealt with many of the points that were made. I could not possibly deal with all of them, but I have tried in the time that you have allotted to me to cover as much ground as possible. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P.K. KUMARAN): Now the discussion on the Budget is over.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWERS TO STARRED QUESTION NO. 397 AND UNSTARRED QUESTION NO. 607 GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 4TH MARCH, 1968 *RE* THE AFFAIRS OF THE ANDHRA STEEL CORPORATION

SHRI M. V. BHADRAM (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, on the 4th March, 1968 the hon. Minister of State in the Ministry of Steel,